सम्पादक की ओर से...

संगठन सर्वोपरि', कहते हैं नितिन गडकरी।

अब वे कहते ही नहीं हैं बल्कि पूरी पार्टी में 'संगठन सर्वोपरि' का महत्व बढ़ा है। दल में आंतरिक लोकतंत्र सदैव बनाए रखने में उनकी एक वर्ष की भूमिका निश्चित ही जनसंघ की याद दिलाती है। उनका कहना है आवश्यकता हो तो चार्टर्ड प्लेन से भी दौरा करना चाहिए परंतु अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। सादगी, समन्वय, समर्पण, सामूहिकता पार्टी के प्राण हैं। वे अनथक यात्री की तरह भारत में संगठनात्मक प्रवास में लगे रहते हैं। उनके एक वर्ष के कार्यकाल से किसी कार्यकर्ता में निराशा का भाव नहीं उपजा। कुशल संगठनकर्ता की यही विशेषता है कि हर कार्यकर्ता को काम मिले। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए नितिनजी सदैव जाने जाते रहे हैं। परन्तु उनकी कार्यशैली की प्रधानता है वे अपने सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों को दल के लिए झोंक देते हैं। राजनीति में रहते हुए कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदना, उनकी चिंता, उन्हें पैरों पर खड़ा करना, इसके वे जीवंत उदाहरण बनकर उभरे हैं। वे व्यवसाय नहीं, प्रकल्प चलाते हैं। और प्रकल्प के नाते उसमें होने वाले आय सभी में बराबर से वितरित होते हैं।

नितिनजी रोने में विश्वास नहीं करते हैं। परिस्थितियां समझते हुए तत्काल निर्णय लेना और सामना करना ही उन्होंने सीखा। एक स्वयंसेवक के नाते उनमें संघबोध सर्वाधिक हैं। परन्तु वे राजनैतिक व्यवहार्यता को भी प्रधानता देते हैं। उनके कार्यकाल का 365 दिन कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक है। झारखंड राज्य को अस्थिरता के दौर से मुक्त करना और वहां सही विकल्प देना, बिहार के चुनाव में भाजपा का 55 सीटों से 91 का होना, यह उनकी कार्यशैली का अनूठा उदाहरण तो माना ही जा सकता है। वे न किसी की बुराई करते और न सुनते हैं। वे 'कमल गोत्र' में विश्वास करते हैं। और उनका मानना है एक ही गोत्र कमल गोत्र। 'पंचनिष्ठा' उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है। वे जातीयता, क्षेत्रीयता को नेस्तनाबूद कर राष्ट्रीयता की राजनीति को जीवंत करने में दिन–रात लगे रहते हैं। डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी जी की राष्ट्रवादी सोच, दीनदयालजी की अंत्योदय की विचारधारा तथा विकास की अवधारणा और सुशासन के संस्कार को पल्लवित करने का कार्य उन्होंने किया है। उनका मानना है कि राजनीति के साथ–साथ कार्यकर्ताओं को अपने पैरों पर खड़ा

होना चाहिए, राजनीति रोजगार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। 'कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ', इस निर्भयता के साथ हत्यारों कार्यकर्ता को जोड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज भाजपा के प्रति प्रत्येक भारतीयों के मन में आत्मविश्वास जगा है। नितिनजी अपने से बड़ों का सम्मान करने में चूकते नहीं और छोटे कार्यकर्ताओं को आगे लाने में पीछे रहते नहीं। जहां वे राजनीति में 'चमचा संस्कृति' की तिलांजलि देने की उद्घोषणा करते हैं वहीं कार्यकर्ता निर्माण पर विशेष जोर देते हैं।

कर्नाटक में उत्पन्न राजनीतिक स्थिति को जिस तरह से नियंत्रण किया, यह उनकी राजनीतिक सूझबूझ का परिचायक है। उनका एक घोष वाक्य है गलती 'मैलाफाइड' है तो माफ नहीं और गलती 'बोनाफाइड' है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वे कार्यकर्ता से आग्रह करते हैं कि नीयत साफ होगा तो नियति तुम्हारे साथ होगा। वे निर्भीकता के साथी हैं। परंतु अनुशासनहीनता के घोर विरोधी है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते श्री नितिन गडकरी ने एक आदर्श कार्यकर्ता का परिचय दिया है। उन्होंने राजनीतिक तामझाम से अपने को दूर रखा है। सुरक्षाकर्मी भले ही उनके साथ हों पर कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। वे राजनीति को तनाव नहीं मानते। अतः वे स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हुए कार्य करते हैं। उनका कार्यकाल भाजपा की जीवन–रेखा को और गहरा करे, कमल संदेश की यही कामना है। आगामी विधानसभा चुनाव और 2014 की लोकसभा की परीक्षा में उनके नेतृत्व में सभी कार्य उत्तीर्ण करने होंगे, इसी विश्वास और कामना के साथ–

çHkkr >k] lkaln
lEikn] dey lans'k

नितिन गडकरी बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

गत 19 दिसम्बर, 2009 को भाजपा के संसदीय दल की बैठक के बाद 52 वर्षीय श्री नितिन गडकरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने श्री गडकरी को बधाई दी।

सभी को साथ लेकर चलेंगे

अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए श्री गडकरी ने पार्टी नेताओं को भरोसा दिलाया कि वह पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने सभी से मार्गदर्शन देने की अपील की और कहा कि नई जिम्मेदारी को लेकर काफी खुश और उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा कि वे विकास की राजनीति करेंगे। पद सम्भालने के बाद श्री गडकरी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके निवास गए।

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रवाद के रास्ते पर पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए कहा कि वे सभी का सहयोग लेंगे और हर स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं का स्नेह पाकर आगे बढ़ने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे।

उन्होंने कहा कि वे अगले तीन साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी का काम देखना सर्वोपरि रहेगा। वे केन्द्रीय राजनीति के लिए नए है और पार्टी ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जिसे वे आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पूरी करने की कोशिश करेंगे।

विधिवत रूप से नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गडकरी निर्वाचित

9 फरवरी 2010। भारतीय जनता पार्टी का अशोक रोड स्थित मुख्यालय– प्रातःकाल से ही हर्षोल्लास और धूमधाम का भव्य दृश्य। कारण– आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का विधिवत रूप से नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाना था। पूरा केन्द्रीय कार्यालय उनके निर्वाचन की घोषणा की प्रतीक्षा में गाजेबाजे और पटाखों की गूंज से प्रतिध्वनित हो रहा था।

आज भाजपा के राष्ट्रीय निर्वाचन प्रभारी श्री थावरचन्द गहलोत को भाजपा के नए अध्यक्ष श्री घोषणा करनी थी, इसलिए भाजपा के वरिष्ठ तथा अन्य नेताओं के साथ पूरा मुख्यालय कार्यकर्ताओं के समूह से भरा पड़ा था।

राजधानी में पिछली रात्रि से बूंदाबांदी का दृश्य छाया हुआ था, फिर भी भाजपा का मुख्यालय पूरी उमंग से परिपूर्ण था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने की प्रक्रिया प्रातः 10 बजे शुरू हुई जब राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री गहलोत ने नामांकन पत्र प्राप्त करना शुरू किया। उन्हें 12 बजे के निर्धारित समय तक कुल 19 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 18 नामांकन पत्र राज्यों से प्राप्त हुए और एक नामांकन पत्र भाजपा संसदीय दल से मिला। इन सभी में एक ही व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव था और वह थे– श्री नितिन गडकरी। श्री गहलोत ने इन सभी नामंकन पत्रों की जांच की और ये सभी ठीक पाए गए। नामांकन पत्र वापस लेने का समय एक बजे निर्धारित था और तब तक कोई भी नामांकन पत्र वापस नहीं लिया गया और इस प्रकार श्री नितिन गडकरी ही एक मात्र प्रस्तावित थे और निर्वाचन अधिकारी श्री थावरचंद गहलोत ने उन्हें निर्विरोध भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। श्री गहलोत ने श्री गडकरी को अपना निर्वाचन–पत्र प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया और श्री गडकरी ने इसे प्राप्त किया।

श्री गडकरी के निर्वाचन की घोषणा का स्वागत और अभिनन्दन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हुआ जिसमें अपार समूह के साथ सभागार में अनेक वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, उनमें भाजपा संसदीय

दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, श्री एम. वेंकैया नायडू एवं श्री बंगारू लक्ष्मण, उपाध्यक्ष श्री बाळ आपटे, श्री शांता कुमार, श्रीमती करूणा शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय सहसंगठन सचिव श्री सौदान सिंह, लोकसभा में विपक्ष के उपनेता श्री गोपीनाथ मुण्डे, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता श्री एसएस अहलूवालिया, महासचिव श्री अनंत कुमार और श्री विजय गोयल, राष्ट्रीय सचिव श्री प्रभात झा, श्री बलबीर पुंज और सुश्री सरोज पाण्डे, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष श्री शाहनवाज हुसैन, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री अमित ठाकर, अनु. जाति मोर्चा अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जटिया, भाजपा मुख्यालय प्रभारी श्री श्याम जाजू, श्री किरीट सोमैय्या, श्री चंदन मित्रा, मीडिया सेल सह–प्रभारी श्री संजय मयूख, अनेक राज्यों के भाजपा अध्यक्ष, भाजपा सांसद, विधायक, मेयर, पूर्व–सांसद तथा पूर्व–विधायक, पूर्व अध्यक्ष एवं महासचिव शामिल थे।

इससे पूर्व पार्टी मुख्यालय आगमन पर श्री गडकरी का पारम्परिक ढंग से स्वागत करते हुए तमिलनाडु उत्तराखंड और पंजाब के सांस्कृतिक कलाकारों ने बड़े धूमधाम के साथ नगाड़े तथा अन्य वाद्य संगीत से पूरे वातावरण में उत्साह भर दिया। इस अवसर पर पटाखों की गड़गडाहट ने पूरे माहौल को गुंजायमान कर दिया। जब गडकरी जी हाल में प्रवेश करने लगे तो गगन ने भी हल्की बूंदे टपका कर उनके स्वागत में शुभ शकुन का परिचय दिया।

चुनाव की घोषणा के बाद श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री एम. वेंकैया नायडू, श्री राजनाथ सिंह और श्री थावरचंद गहलोत ने श्री नितिन गडकरी को मंच पर लेकर गए।

अपने उद्‌बोधन में श्री गडकरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित करने पर अपना आभार प्रगट किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर आसीन होने पर गौरव महसूस कर रहा हूं जिसे पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जैसी महान विभूतियों ने सुशोभित किया था। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान, उत्तरदायित्व और चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे मैं अपनी भरपूर क्षमता और अपने वरिष्ठ नेताओं के समर्थन, सहायता और मार्गदर्शन से पूरा करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं पार्टी में अपने कई नेताओं से करिष्ठ हूं और मैं विनम्रतापूर्वक अपने सभी वरिष्ठजनों का आदर करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे सभी निर्णय अपने सभी सहयोगियों के परामर्श और मार्गदर्शन से सामूहिक रूप से लिए जाएंगे।

उन्होंने इस बात पर गर्व किया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, जिसमें मेरे जैसा साधारण सा कार्यकर्ता, जिसने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत दीवारों पर पोस्टर चिपका कर और लिखने से की, वह आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है। मैं न तो किसी प्रधानमंत्री का पुत्र था और न ही किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाती होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर भी आज मुझे अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है, यह गौरव की बात है और यही सिद्ध करता है कि भाजपा की पहचान अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग है। पिछले पांच सप्ताहों में, इस पद पर रहते हुए मैंने सभी की सहमति से पार्टी में आम सहमति बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कोई समस्या आती थी तो मैं श्री आडवाणी, श्री अरूण जेटली, श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उस पर चर्चा करता था।

श्री गडकरी ने कहा कि हमें पार्टी को और उच्च शिखर तक ले जाना है और यह आप सभी की सहायता और समर्थन से ही संभव हो पाएगा। जब श्री गडकरी सभागार से बाहर निकले तो बादल छंट गए थे और सूर्य अपनी आभा लेकर प्रगट हो गया था, जैसे संदेश दे रहा हो कि उनके नेतृत्व में पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। ■

नितिन गडकरी : एक परिचय

- अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र (2004 से 2009)
- प्रतिपक्ष के नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद (1999–2005)
- लोक निर्माण कार्यमंत्री, महाराष्ट्र (1995–1999)
- जन्मः 27 मई 1957, नागपुर, भारत
- शैक्षिक योग्यताः एम कॉम, एलएलबी, डीबीएम
- 1989 में ग्रेज्युएट निर्वाचन क्षेत्र नागपुर क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्वाचित। 1990, 1996, 2002 (निर्विरोध), 2008 में पुनः निर्वाचित।
- महाराष्ट्र के लोकनिर्माण कार्य मंत्री– 27 मई 1995
- सदस्य, निजीकरण की उच्च अधिकार प्राप्त समिति, महाराष्ट्र सरकार (1995–99)
- चेयरमैन, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (1995–99)
- नागपुर जिला के गार्डियन मंत्री (1995–99)
- चेयरमैन, खनन नीति कार्यान्वयन समिति, महाराष्ट्र सरकार (1995–99)
- चेयरमैन, महानगर (मेट्रोपालिस) सौन्दर्यीकरण समिति, महाराष्ट्र सरकार (1995–99)
- चेयरमैन, राष्ट्रीय ग्रामीण सडक विकास समिति और चेयरमैन, सीपीडब्ल्यूडी समीक्षा समिति, भारत सरकार
- विदेश यात्रा– इस्रायल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यू.के., स्विट्जरलैण्ड, जापान, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्राजील और श्रीलंका– विभिन्न शिष्टमंडलों के सदस्य रूप में।
- श्री गडकरी ने औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास के माध्यम से दलितों के पुनरूद्धार के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए विकास कार्य में लगे रहे।
- श्री गडकरी ने विकास की कोरी बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी उद्यमशील कुशलता का प्रदर्शन किया। वे एक सेवानिष्ठ किसान (कृषिविद्) हैं, जिनकी सदैव जल प्रबंधन,

सौर–उर्जा परियोजना और कृषि की आधुनिक तकनीकों में रूचि रही है, जिससे वे आज एक सफल चीनी फैक्टरी के चेयरमैन हैं।

- श्री गडकरी खेलों के प्रति उत्साही रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से क्रिकेट में रूचि रही है।
- कंचन के साथ विवाह, दो पुत्र– निखिल और सारंग– एवं पुत्री केटकी।
- श्री गडकरी कभी भी क्षुद्र राजनीति में नहीं फंसे। उनके लिए विकास और प्रगति ही परम उद्देश्य रहा। दलितों का उद्धार मिशन रहा। 50वें जन्मदिवस पर लोगों ने जितनी स्नेह वर्षा से उन्हें अभिसिंचित किया, वह अभूतपूर्व थी। नागपुर का लोकप्रिय सामाजिक स्थल चिटनिस पार्क उनके प्रशंसकों से भरा पड़ा था जिनमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों के वे गरीब लोग थे जो स्वयं अपना पैसा खर्च कर वहां पहुंचे थे। एक सर्वदलीय समिति ने इस समारोह का आयोजन किया था जो नागपुर की एक अपूर्व ऐतिहासिक यादगार बन गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री गडकरी को विदर्भ भूषण और नागभूषण से सम्मानित किया गया, जिन क्षेत्रों में वे अत्यंत सम्मानीय रहे हैं।
- 1995 में लोक निर्माण कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) का मंत्री पद संभालते ही उन्होंने इस विभाग की शक्ल–सूरत बदलनी शुरू कर दी थी। उन्होंने घोषणा की थी कि मुझे अपने विभाग के इंजीनियरों पर पूरा भरोसा है, जिससे इंजीनियरों में परिश्रम करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने इतने आश्चर्यजनक परिणाम देकर दिखाए जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे।
- श्री गडकरी ने महाराष्ट्र में 13736 गांवों को 'हर मौसम में जोड़ने वाली सड़कों' का निर्माण कार्य किया। उन्होंने देखा कि ये सड़कें स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी जोड़ी नहीं गई थीं। उन्होंने यह भी देखा कि अगर वार्षिक बजटों पर ही इनका निर्माण होगा तो शायद 350 वर्षों में भी इनका निर्माण पूरा न हो पाए। क्योंकि सरकारी खजाने से धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने 'नाबार्ड' के अधिकारियों को समझाया और ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए उदार शर्तों पर 700 करोड़ रूपए का ऋण जुटाया। साथ ही साथ, उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजीकरण को भी साथ लिया, जिससे भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का नया रास्ता खुला। बहुत ही परियाजनाएं निजीकरण के माध्यम से ली गई। 4 वर्षों के अंदर ही पर्याप्त धन उपलब्ध करके लगभग 98 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए 'राउण्ड–दि–ईयर रोड कनेक्टिविटी' अर्थात् पूरे वर्षभर सड़क योजना को पूर्ण कर दिखाया। इस सफतला से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होंने उन्हें एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर उनसे भारत के लिए भी इसी प्रकार की योजना तैयार करने को कहा।
- श्री गडकरी नक्सलवादी क्षेत्रों में भी पहुंचे जहां नक्सलवादी सड़क निर्माण करने नहीं देते थे। उन्होंने सीमा सड़क संगठन (बीआओ) की सहायता ली ताकि वहां सड़कें और पुल बनाए जा सकें और इस प्रकार आदिवासियों को सहज और स्थायी सड़कों पर चलने की सुविधा मिल सके।
- श्री गडकरी ने अमरावती जिले की मेलघाट–घरनी पट्टी में आदिवासियों के कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए सड़कों के निर्माण के लिए एक अनूठे समाधान का प्रयोग किया। सड़कों की पहुंच न होने से आदिवासियों को चिकित्सा सहायता, राशन और शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। श्री गडकरी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस पट्टी के दूरदराज के 91 गांवों के लिए हर मौसम में काम वाली सड़कों को जोड़ा। इस क्नेक्टिविटी से इस पट्टी की सामाजिक– आर्थिक हालत ही बदल कर रख दी और कुपोषण की घटनाओं को कम करने

पर नाटकीय रूप से प्रभाव पड़ा।

- श्री गडकरी को 'मुम्बई भूषण' (प्राइड आफ मुम्बई) एवार्ड से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने मुम्बई में यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए कई लाई ओवर पुलों, अनेक सड़कों का विस्तार, भूमिगत पथों और रेल पुलों को निर्माण कर पूरे महानगर की शक्ल ही बदल कर रख दी थी। उन्होंने ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बहुमंजिली पार्किंग स्थलों की कल्पना की थी। वर्ली बांद्रा सी–लिंक परियोजनाओं के जन्मदाता भी वही थे। लव ग्रोव जंकशन और महिम जैसे जोड़ने वाले प्रमुख लाई–ओवर पुल भी गडकरी के जमाने में ही लगभग पूरे होने वाले थे। एप्रोच सड़कों के कंक्रीटीकरण का काम भी तभी शुरू हुआ था। श्री गडकरी ने न्हावा शेवा–सेवरी सी–लिंक परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति दी थी, जो तब से रूकी पड़ी थी जब से मंत्रालय बना था। मुम्बई को सुख–चैन की नगरी बनाना था उनका सपना, परन्तु दुर्भाग्य से, स्थिति दूसरी तरफ मुड़ गई।
- श्री गडकरी ने पीडब्ल्यूडी को चुस्त दुरूस्त किया और इस सरकारी विभाग में पहली बार कम्प्यूटर का उपयोग शुरू हुआ। उनके कार्यकाल के कर्मचारियों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरह काम करना शुरू किया। सड़कों पर बड़ी संख्या में घातक दुर्घटनाओं को देखते हुए श्री गडकरी ने महाराष्ट्र में दुर्घटना–वाले स्थलों के अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई। इसने लगभग 25000 स्थलों की पहचान की जहां दुर्घटना में मूल्यवान जीवन समाप्त हो जाते थे। उन्होंने प्रारम्भिक रूप से 20 करोड़ के बजट से समिति की सिफारिशों को अमल में लाया। तुरंत ही दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई। इस प्रकार का काम न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि भारत में पहली बार सम्पन्न हुआ। 250 करोड़ रूपए से अधिक खर्च कर पीडब्ल्यूडी ने इन अत्यंत खतरनाक स्थलों को सुधारा।
- महाराष्ट्र विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री गडकरी ने सदा ही सरकार को कटघरे में खड़ा रखा है। उन्होंने अनेकों बड़े–बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया और सदन में बड़े–बड़े मुद्दे उठाए। उन्हें नवम्बर 2004 में भाजपा का महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष चुना गया और दिसम्बर 2006 में उनका पुनर्निवाचन हुआ। नीचे से ऊपर तक पार्टी संगठन का पुनर्निर्माण उनके लिए प्रथम चुनौती थी। श्री गडकरी ने अपने कठोर परिश्रम से कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा किया और कामकाज को पारदर्शी बनाया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने महाराष्ट्र के कोने–कोने में अपना विस्तार किया। श्री गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कम से कम अपने क्षेत्र में एक सामाजिक/स्वैच्छिक परियोजना से सहबद्ध होना चाहिए, और इससे अच्छा लाभ मिला। लोगों तक पहुंच बनाने से पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया में तेजी आई है।
- श्री गडकरी का अपवंचितों को शक्तिशाली बनाने में बहुत गहरा योगदान किया है। पार्टी की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भारत के प्रति उनका प्रेम सर्वोपरि रहा है। नेतृत्व को उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है कि वे पार्टी को वर्तमान स्थिति से उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने में सफल होंगे। वे जनता जर्नादन के सच्चे नेता हैं जिस पर पार्टी को गर्व है।

प्रेस विज्ञप्तियां

राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, सुशासन साधन, अंत्योदय उद्देश्य

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 24 दिसम्बर, 2009 को नई दिल्ली में अपनी पहली प्रेस कांफ्रेस में जारी किया गया वक्तव्य

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली प्रेस कांफ्रेस में राष्ट्रीय मीडिया जगत के मित्रों से मिलने पर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को आनंददायी क्रिसमस दिवस की और समृद्ध – 2010 की शुभकामना देना चाहता हूं। मैं हमारे प्रेरणास्रोत आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उनके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूं।

पार्टी द्वारा इस नए महान उत्तरदायित्व को सौंप कर जो भरोसा और विश्वास मुझ में व्यक्त किया गया है, उससे मैं पूर्णतः अभिभूत हूं। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है कि मेरे कंधों पर एक भारी उत्तरदायित्व आ गया है। किंतु, मेरी पार्टी के किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए कोई कार्य असाध्य नहीं है, यदि वह पार्टी की मूल विचारधारा और आदर्शवाद के प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प ले लेता है जैसाकि डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में साक्षात अभिव्यक्त हुआ था; यदि वह हमारे समकालीन दो शीर्षस्थ नेताओं – श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लालकृष्ण आडवाणी की प्रेरणादायी विरासत से निर्देशित होता रहता है, यदि वह टीम वर्क और अनुशासन के माहौल में अपने से वरिष्ठ तथा कनिष्ठ सहयोगियों से सीखने की उत्सुकता दर्शाता है जोकि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की सदैव से ही परंपरा रही है, और यदि वह अपने साथी कार्यकर्ताओं की विराट सेना, जिसमें पार्टी की सबसे छोटी और दूरस्थ इकाइयों के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, से शक्ति ग्रहण करता है तथा बदले में उन्हें शक्ति प्रदान करता है।

मैं प्रथम और सर्वप्रथम एक कार्यकर्ता हूं। मैं जानता हूं और आज इसकी पुनः पुष्टि करता हूं कि मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं की राष्ट्र तथा पार्टी के लिए अथक त्याग–भावना और संघर्ष मेरी पार्टी की दृढ़ता के सबसे बड़े आधार हैं। जहां तक संगठन का सवाल है अनुशासन, दृढ़ संकल्प, परस्पर विश्वास एवं सम्मान यह हमारी कार्य पद्धति की आधारशिला होगी।

विचारधारा का आधार राष्ट्रवाद :

भाजपा 'भारत प्रथम' सूत्र पर काम करने वाला दल है। हम भाजपा को राष्ट्र निर्माण के एक उपकरण के रूप में देखते हैं।

मेरी पार्टी की विचारधारा का आधार राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद रहेगा और यही मेरी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रेरणास्रोत भी बना रहेगा। भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति में निहित हैं, जो समावेशी भी है और समन्वित भी और वही प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतीय की प्ररेणा का स्रोत भी है। भाजपा वास्तविक सर्वधर्मसमभाव के प्रति प्रतिबद्ध है, वोट–बैंक की पंथ निरपेक्षता के जैसी नहीं। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा नस्ल के आधार पर भारत के नागरिकों के बीच भिन्नता और भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत सबका है और सभी भारत के, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही सभी का भारत को सुदृढ़ और एकी.त बनाने का समान दायित्व भी है।

अतः भाजपा उस हर नीति और उस हर प्रयास का विरोध करती रहेगी, जिससे राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना हो। हमारा विरोध जम्मू और कश्मीर में पनपता अलगाववाद तथा असम एवं देश के अन्य भागों में अवैध घुसपैठ, जिसे कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के तहत प्रोत्साहित किया है, के प्रति हमारा विरोध भारत की एकता और सुरक्षा के लिए सदैव है।

आतंकवाद और नक्सलवाद का संपूर्ण विरोध :

भारत की एकता और सुरक्षा के प्रति ऐसी ही चिंता मुझे आज अपनी पार्टी की वही अविचल स्थिति स्पष्ट करने के लिए विवश कर रही है कि भारत को आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों में लिप्त डेविड कोलमैन हेडली जैसे अंतर्राष्ट्रीय जेहादी षड्यंत्रकारी द्वारा भारत के खुफिया भेद लेने के लिए बार–बार किए गए दौरों के बारे में हाल के खुलासों और प्रधान कमेटी रिपोर्ट में निकाले गए चिंताजनक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि हमारी सुरक्षा प्रणाली में ऐसी खामियां मौजूद हैं, जिनका लाभ राष्ट्र के शत्रु कभी भी उठा सकते हैं। आतंकवाद की तरह ही माओवाद की राष्ट्र विरोधी विदेशी विचारधारा से प्रोत्साहित हुआ नक्सलवाद भी अनेक अबोध जिंदगियों को निगल रहा है, जिसमें हमारे सुरक्षाकर्मियों की जिंदगियां भी शामिल हैं। मेरा संप्रग सरकार से अनुरोध है कि वह इस दोहरे संकट के साथ दृढ़ता से निपटे और मैं इस दिशा में उठाए गए हर उचित कदम के प्रति अपनी पार्टी के समर्थन का विश्वास व्यक्त करता हूं।

राजनीति, सामाजिक-आर्थिक सुधारों और राष्ट्र निर्माण का साधन :

जहां मैं राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हूं, जिसने मुझे राजनीति की तरफ आकर्षित किया है, वहीं भारत की समृद्धि और इसके सभी लोगों के कल्याण मेरे वैचारिक विश्वास के मूल में है। सार्वजनिक जीवन में मेरे बाद के अनुभव और विधायक तथा मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल ने मेरे इस विश्वास को और अधिक दृढ़ कर दिया है कि राजनीति शक्ति हेतु छीना–झपटी का मैदान नहीं बन सकती, बल्कि इसको सामाजिक–आर्थिक सुधार और राष्ट्र–निर्माण का साधन बनना चाहिए। मेरा विश्वास है कि वह समय आ पहुंचा है जब भारत को विकास पर पूरा ध्यान केन्द्रित करना होगा। भाजपा का समतावादी विकास में विश्वास है। इसकी प्राप्ति के लिए हमारी पार्टी आंतरिक निष्पादन परीक्षा–तंत्र विकसित करने का प्रयास करेगी, ताकि जहां–जहां भी भाजपा सत्ता में है वहां–वहां हर स्तर पर सुशासन सुनिश्चित हो सके।

खेद की बात है कि कांग्रेस ने उस पथ का अनुसरण किया है, "जहां कुछ लोगों का विकास हो तथा शेष वंचित"। यह निश्चय ही असमर्थनीय भी है और खतरनाक रूप से अस्थिरकारी भी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉ. सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति का हाल का यह खुलासा चेतावनी का संकेत है कि भारत में गरीबों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि ग्रामीण भारत में गरीबी 42 प्रतिशत है न कि 28 प्रतिशत जैसाकि पूर्व में अनुमान लगाया गया था। गरीब लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों की दुर्दशा को आसमान छूती मूल्यवृद्धि ने और अधिक बढ़ा दिया है – उस दुर्दशा को जिस पर काबू पाने में संप्रग पूरी तरह विफल हुआ है।

इस वास्तविकता को बदलना किसी भी राजनीतिक स्थापना का पहला कर्तव्य होता है। अतः मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वे अपने वंचित भाई–बंधुओं के चेहरों पर मुस्कान लाने की इच्छा से अभिप्रेरित हों, वे उन किसानों का संकट समाप्त करें, जिन्होंने हजारों की संख्या में आत्महत्याएं कर ली हैं, वे उस कुपोषण का उन्मूलन करें, जो हजारों जनजातीय बच्चों को काल का ग्रास बना रहा है, वे हमारे प्रतिभाशाली युवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें।

अंत्योदय के प्रति प्रतिबद्धता :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शितापूर्ण प्रधानमंत्रित्व के अंतर्गत भाजपा–नीत राजग सरकार ने जनादेश का विकास की गति बढ़ाने तथा उसे व्यापक करने के लिए उपयोग किया था। आज मैं अपनी पार्टी के विकास दर्शन को निम्नलिखित नारे में संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना चाहूंगा : राष्ट्रवाद अब हमारी प्रेरणा है, सुशासन द्वारा विकास हमारा साधन है और अंत्योदय (जिसका अर्थ है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े तथा अन्य दुर्बल वर्गों सहित अत्यधिक वंचित लोगों को अग्रता प्रदान करना) हमारा उद्देश्य है। इस नारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की ठोस अभिव्यक्ति के रूप में भाजपा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वह अपने कार्यक्षेत्र में कम से कम एक विकास और सेवा प्रकल्प से संबद्ध हो।

आगामी तीन वर्षों में भाजपा सुदृढ़तर होकर उभरेगी :

मैं इस बात को अधोरेखित करना चाहूंगा भाजपा सुशासन, गतिशील तथा सर्वसमावेशक विकास और आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को प्रतिबद्ध एक स्वाभाविक शासक दल है। कांग्रेस का एकमात्र विकल्प है। भाजपा को गर्व है कि उसने भारत के राजतंत्र को कांग्रेस की प्रधानता वाली एक ध्रुवीय प्रणाली से दो ध्रुवीय प्रणाली में रूपांतरित कर दिया है। भाजपा को इस बात पर भी गर्व है कि उसने उस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किया था, जिसने ऐसा प्लेटफार्म प्रदान किया, जिस पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से इतर सभी पार्टियों का स्वागत हुआ था। मेरा उद्देश्य यह देखना है कि आगामी तीन वर्षों में भाजपा उन राज्यों में, जहां वह पारंपरिक रूप से सुस्थापित है और जहां उसकी अब तक उपस्थिति हाशिये पर बनी हुई है, और अधिक मजबूत बनकर उभरे। इसी के साथ–साथ भाजपा राजग को और अधिक विस्तार देने तथा मजबूत करने के लिए भी प्रयास करेगी ताकि वह प्रतिपक्ष की एकता हेतु एक मजबूत मंच बन सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली अपेक्षा यह है कि सभी स्तर पर भाजपा का पार्टी संगठन मजबूत हो। पार्टी का भौगोलिक विस्तार करना और उसको और अधिक एकत्व तथा मजबूती प्रदान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी।

अंततः जो लोग मुझे पुष्प या पुष्पहार देना चाहते है उनसे मेरी अपील है कि उतनी धन राशि किसान सहायता कोष में जमा करें, जिसे आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाए। ■

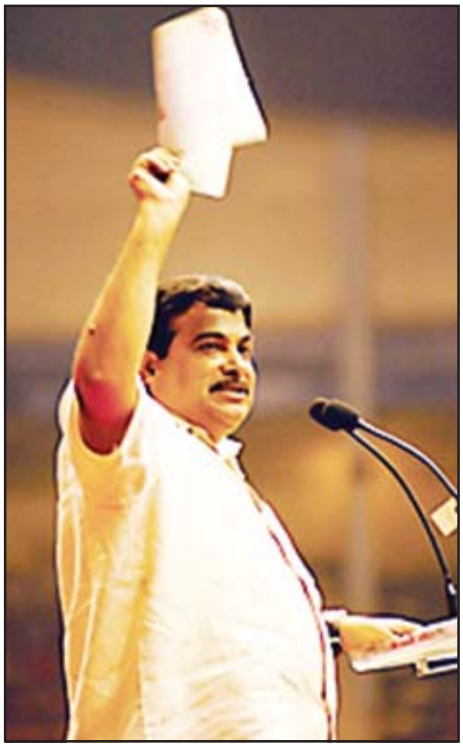

महंगाई, गरीबी और खाद्य संकट

भाजपा अध्यक्ष ने पूछे प्रधानमंत्री से 14 प्रश्न

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से 1 अप्रैल, 2010 को बेलगाम महंगाई के मुद्दे पर 14 प्रश्न पूछे।

पिछले 20 सप्ताहों में खाद्य मुद्रास्फीति 17 से 20 प्रतिशत रही

1. आखिर गलती कहां हुई है?

   भारत में 11 प्रतिशत की मुद्रास्फीति विश्व में सबसे अधिक है। यदि देखें तो चीन की जीडीपी वृद्धि 9.5 प्रतिशत (भारत की 7.2 प्रतिशत) रही, फिर भी चीन की मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत और भारत की 11 प्रतिशत रही।

2. क्या आप इस बात से इंकार करते हैं कि विश्व की 1 से 2 प्रतिशत मुद्रास्फीति के मुकाबले भारत की मुद्रास्फीति 11 प्रतिशत है?

   अन्य देशों की तुलना में भारत में चीनी की कीमतों में दुगुनी और गेहूं की कीमतों में 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

3. क्या यह सच नहीं है कि विश्व बाजार की तुलना में खाद्य पदार्थों की कीमतें 80 प्रतिशत से

अधिक है?

4. क्या यह असलियत नहीं है कि आपके शासन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में दोगुनी वृद्धि हुई।

5. क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि दलितों और मध्य वर्गीय लोगों के लिए गुजारा करना तक मुश्किल हो गया है?

48 लाख टन चीनी का निर्यात 12.50 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर किया गया और इसका पुनः आयात 22 से 32 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर हुआ।

6. आपने चीनी का निर्यात 12.50 रूपए प्रति कि.ग्रा. करना और 22 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर आयात करना बेहतर समझा परन्तु बफर स्टॉक बनाना ठीक नहीं समझा। क्या आप लोगों के सामने इस बारे में जवाबदेह नहीं है?

7. क्या आप अपनी इस घोटालेबाज निर्यात–आयात नीतियों से नावाकिफ रहे हैं?

''योजना आयोग ने अपनी 2005 की रिपोर्ट में बीपीएल (गरीबी के नीचे रहने वाले लोगों की) जनसंख्या को 31 करोड़ बताया था। तेन्दुलकर समिति की दिसम्बर 2009 में से 42 करोड़ बताया था और फिर भी आपका दावा रहा है कि गरीबी घटी है''।

8. फिर ऐसा क्यों है कि ग्रामीण भारत के 42 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है? क्या आप सचमुच उन्हें खाद्यान्न दे रहे हैं?

9. सरकारी गोदाम खाद्यान्नों से आवश्यकता से अधिक भरे पड़े हैं और सड़ रहे हैं। फिर भी कीमतें क्यों आसमान छू रही हैं और क्यों गरीब लोग पेटभर खाना भी नहीं खा पाते हैं?

10. क्या यह सच नहीं है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्सेना कमेटी ने बताया था कि 51 प्रतिशत गरीब लोगों को बीपीएल राशन कार्ड नहीं दिए गए और उन्हें खाद्यान्नों से वंचित रखा गया?

दिसम्बर 2009 में कृषि नकारात्मक– 0.2 प्रतिशत रही। इसके बाद भी सरकार ने कृषि विकास के लिए अपने कुल 12 लाख करोड़ बजट में से मात्र मामूली सा 900 करोड़ रूपए अर्थात् 0.075 प्रतिशत का प्रावधान किया।

11. आपको इस सम्बन्ध में क्या कहना है?

12. ऐसा क्यों है कि किसान को सबसे कम मिलता है, तो उधर आम आदमी को सबसे ज्यादह चुकता करना पड़ता है?

नेशनल कामोडिटी एक्सचेंज– एनसीडीईएक्स में 2009 में 8,03,842 करोड़ के कुल उत्पादन में से मात्र 0.28 प्रतिशत अर्थात् 2243 करोड़ रूपए की सुपुर्दगी हो पाई।

13. तिकड़मबाजी वाली बिक्री। मांग कीमतें बढ़ा रही हैं। आखिर आप इसका लाभ किसे पहुंचाना चाहते हैं?

सट्टेबाजों को? तिकड़मबाजों को?

बहु–राष्ट्रीय कम्पनियों को?

सरकार के मंत्री खाद्य–कमियों/कम उत्पादन के बारे में खामख्याली के बयान देते रहते हैं।

14. खाद्य उत्पादन की कमियों के बारे में कल्पनात्मक भविष्यवाणियां करके आप किन निहित स्वार्थी लोगों के हित साध रहे हैं?■

केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से बढ़ी महंगाई

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 2 जुलाई 2010 को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर 5 जुलाई को ''भारत बंद'' कार्यक्रम हेतु देशवासियों से समर्थन की अपील की।

पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की कीमतें बढ़ने से आम आदमी परेशान है और देश की जनता में इस कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के इस जन–विरोधी निर्णय के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। महंगाई के खिलाफ आम जनता में जागरूकता पैदा करने व केन्द्र सरकार को बढ़े हुए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी करने के उद्देश्य से देशभर में भाजपा सड़कों पर उतरी है। भाजपा सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेगी। भाजपा ने गत 25 जून से ही विरोध कार्यक्रम की शुरूआत कर दी है। देशभर के 428 जिला मुख्यालयों में धरने–प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें 5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी क्रम में 30 जून, 1 जुलाई व 2 जुलाई को देशव्यापी "भाजपा महंगाई विरोधी जन आंदोलन" कार्यक्रम आयोजित हुआ। देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली, धरना प्रदर्शन व गिरफ्तारी देकर अपना जबरदस्त विरोध जताया है। यह विरोध कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा और इस कड़ी में 5 जुलाई को भारत बंद का आयोजन किया गया है। भाजपा का मंहगाई के विरूद्ध एक हस्ताक्षर अभियान देशभर में चल रहा है। मानसून सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी 10 करोड़ लोगों का मंहगाई विरोधी हस्ताक्षरित ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को सौंपेंगी।

कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीति, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण आम जनता की बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आम जनता महंगाई की मार से बेहाल हो चुकी है। यूपीए सरकार की जन–विरोधी नीतियों के कारण देश में एक आतंक का माहौल दिखाई देने लगा है। देश के अंदर पिछले साल और इस साल गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। सरकारी आंकड़ों द्वारा चीनी का उत्पादन 1 लाख 78 टन के करीब हुआ है। कांग्रेस राज में गरीब भूखा मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे है और 58 हजार करोड़ का गेहूं एफसीआई गोदामों में सड़ रहा है। अन्य देशों की तुलना में भारत में चीनी की कीमतें दुगनी है। आज विश्व बाजार की तुलना में भारत में खाद्य पदार्थों की कीमतें 80 प्रतिशत से अधिक हैं। यह सरकार का कुप्रबंधन नहीं तो और क्या है? दिसम्बर, 2009 में कृषि उत्पादन दर 0.2 प्रतिशत रही है उसके बावजूद भी सरकार ने कृषि विकास के लिए अपने कुल 12 लाख करोड़ के बजट में से मामूली–सा मात्र 0.07 प्रतिशत यानि सिर्फ 900 करोड़ का प्रावधान किया। किसान जब अपनी फसल पैदा करता है तो उसको उसकी कीमत कम मिलती है, दूसरी तरफ ग्राहक के रूप में वही वस्तु खरीदने जाता है तो उससे अधिक कीमत वसूली जाती है। आम जनता में इस सरकार की तानाशाही रवैये के प्रति घोर निराशा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आम जनता के साथ कांग्रेस का हाथ का नारा देने वाली यह सरकार आम जनता से और कितना विश्वासघात करेगी?

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि महज सौ दिन में ही हम महंगाई कम कर देंगे। वह महंगाई, जिसकी मार आम जनता यूपीए–I के शासनकाल के अंतिम वर्षों में झेल

रही थी। यूपीए–II के शासन के सौ दिन पूरे हुए और महंगाई कम होने की बजाय कई गुना बढ़ गई। एक वर्ष पूरे होने के पश्चात् भी महंगाई की रफ्तार घटने के बजाय बढ़ती ही चली गई। गत अप्रैल माह में हमने इस सरकार से बढ़ती हुई महंगाई को लेकर 14 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। तथा इस सरकार से महंगाई के संदर्भ में श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की थी। किंतु, इस कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने आम जनता के हितों से जुड़े इन प्रश्नों की अनदेखी करते हुए महंगाई को कम करने का कोई भी प्रयास नहीं किया।

इस बढ़ती हुई महंगाई ने देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता की कमर तोड़ दी है। सरकार को यह भी नहीं पता कि इस देश में कितने गरीब है। योजना आयोग के अनुसार यह संख्या 27 प्रतिशत है। ग्रामीण विकास की एन.सी. सक्सेना कमेटी के अनुसार कैलोरी के आधार पर देश में 50 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है और असंगठित क्षेत्र के लिए गठित अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार देश के 77 प्रतिशत लोग 20 रूपए प्रतिदिन पर जीविका जीते है। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 37.2 प्रतिशत है। सरकार साफ–साफ यह बताए कि आखिर इस देश में गरीबों की संख्या कितनी हैं ? वहीं योजना आयोग ने अपनी 2005 की रिपोर्ट में बीपीएल जनसंख्या को 31 करोड़ बताया था। तेंदुलकर समिति ने दिसम्बर, 2009 में इसे 42 करोड़ बताया फिर भी सरकार दावा कर रही है कि गरीबी घटी है। ग्रामीण भारत के 42 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और सरकार उनको खाद्यान्न देने में असमर्थ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 में बीपीएल परिवारों की संख्या इस देश में लगभग 28 करोड़ थी जो कि बढ़कर करीब 41 करोड़ हो गई है। इन लोगों की आमदनी लगभग 20 रूपए प्रतिदिन से भी कम है। इसके लिए कांग्रेस की जन–विरोधी नीतियां जिम्मेदार है। ऊपर से बेलगाम बढ़ती महंगाई ने इन परिवारों के बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया है। इस सप्ताह खाद्य मुद्रास्फीति की दर 12.92 फीसदी दर्ज की गई है, जिसे गत सप्ताह की तुलना में 4 फीसदी की कमी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन, योजना आयोग के प्रधान सलाहकार प्रणव सेन ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में तेज गिरावट की मुख्य वजह बीते साल की इसी अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति का आधार ऊंचा होना है। वास्तव में ज्यादातर खाद्य वस्तुएं महंगी बनी हुई हैं। यहां यह भी ध्यान रखने योग्य है कि हाल ही में डीज़ल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी का असर आगामी सप्ताह में खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर देखने को मिलेगा, जिससे महंगाई और अधिक बढ़ेगी।

पेट्रोल और डीज़ल के दामों में इस सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया है वह बयान इस सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। आम जनता में घोर निराशा है। भाजपा उनके इस संवेदनहीन बयान की भर्त्सना करती है।

केन्द्र सरकार जवाब दे

ge ljdkj ls ;g iNuk pkgrs gSa fd %

- क्या प्रधानमंत्री को केवल ऑयल कंपनियों की खस्ता हालत दिखती है और जनता की खस्ता हालत नहीं दिखती?
- सरकार बताए की उनकी प्राथमिकता क्या है ? आम आदमी या ऑयल कंपनी?
- सरकार यह बताए कि दो साल से लगातार वादे करने के बावजूद वह महंगाई को क्यों नहीं रोक पाई?
- क्या सरकार को पता है खाद्यान्न कीमतों का सूचकांक जहां नरमी के संकेत दे रहा है वहीं बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं?
- महंगाई कम करने के लिए यूपीए सरकार कौन–सा सफल और कारगर कदम उठाया है?
- श्रीमती सोनिया गांधी बताए कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री महंगाई रोकने में नाकाम क्यों हो रहे हैं?
- श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी महंगाई के मुद्दे पर क्यों चुप है, देश जानना चाहता है?

राष्ट्रमंडल खेल : भारी भ्रष्टाचार संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 19 अक्तूबर, 2010 को जारी प्रेस वक्तव्य

हमारे खिलाड़ियों ने हाल ही में सम्पन्न हुए 19वें राष्ट्रमंडल खेलों – दिल्ली 2010 में विभिन्न क्षेत्रों में अपने शानदार प्रदर्शन से भारत को गौरवांवित किया है। खेल संस्कृति पैदा करने की भारत की क्षमता और एक खेल प्रधान देश बनने के बारे में सभी प्रकार की अनिश्चिताएं उस समय समाप्त हो गई जब पदकों की संख्या पहली बार 3 अंकों में पहुंची। उद्घाटन तथा समापन समारोह वास्तव में भव्य थे और इसके साथ–साथ सुरक्षा प्रबंध भी त्रुटिविहीन थे। मैं सभी भारतीय खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और उन खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पदक जीते हैं। मैं एथलीटों के विरूद्ध कुछ ग्रुपों द्वारा आतंकी हमले करने की धमकियों की आसूचना रिपोर्टों के बावजूद राष्ट्रमंडल खेलों में पूर्ण सुरक्षा बरतने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सलाम करता हूं। मैं खेलों को पूरी तरह सफल बनाने में भाग लेने वाले कलाकारों, स्कूली बच्चों तथा अन्य सभी व्यक्तियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है।

बिड जीतने तक सब कुछ ठीक–ठाक प्रतीत होता था। उसके बाद हम कहां असफल हुए और वे सब कौन हैं, जिन्होंने हमें बदनाम किया ? सामान्य रूप से सारा विश्व और विशेष रूप से भारत की जनता यह जानना चाहती है।

भारत ने नवम्बर, 2003 में बिड जीती थी और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति बनाने में 16 महीने का समय लगा। इस समिति में राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, ज्योतिर्आदित्य सिंधिया, अजय माकन, जितिन प्रसाद और संदीप दीक्षित सहित 35 सदस्य थे।

आधारभूत ढांचा समन्वय समिति की पहली बैठक 15 मार्च, 2005 को दिल्ली में हुई, जिसमें स्टेडियम तथा उनके अपग्रेडेशन और खेल गांव के निर्माण संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया गया और इन सभी कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से समझौता किए बिना पूरा करने के लिए सभी सरकारी निकायों जैसे कि शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार तथा अन्य एजेंसियों को 5

वर्ष से अधिक का समय दिया गया। उनके प्रस्तावों को मंत्रियों के एक ग्रुप द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और बाद में केन्द्रीय मंत्रिमंडल का अनुसमर्थन प्राप्त हुआ। इन परियोजनाओं के लिए टेंडर मंगाने की प्रक्रिया में अनियमितताएं तथा गड़बड़ी हुई, जिनमें कई हजार करोड़ रूपए की राशि शामिल है।

राष्ट्रमंडल खेलों में कदाचारों तथा भ्रष्टाचार संबंधी पहली कहानी का 30 जुलाई, 2010 को पता चला जब यू.के. की एक कम्पनी ए.एम. फिल्म्स ने बिना किसी लिखित करार के भुगतानों का मामला उजागर किया। ऐसा आरोप है कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति ने ए.एम. फिल्म्स जोकि लंदन में एक भारतीय–स्वामित्व वाली फर्म है, को बिना टेंडर मांगे और बिना कागजी कार्यवाही किए गत वर्ष के दौरान क्वीन्स बैटन रिले उद्घाटन समारोह के लिये किए गये कार्यों हेतु 4,50,000 पाउंड से अधिक (30 मिलियन रूपये से अधिक) की राशि का भुगतान किया।

खेलों की विभिन्न परियोजनाओं, जिनमें स्टेडियम तथा अन्य आधारभूत ढांचा शामिल है, के लिए टेंडर देने तथा एअरकंडीशनर, ट्रेडमिल्स और टॉयलेट पेपर जैसे उपकरणों को किराए पर लेने या खरीदने के लिए ठेके देने में भ्रष्टाचार अपनाया गया प्रतीत होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने खेलों के लिए बनाए जा रहे/नवीकरण किए जा रहे स्टेडियम पर होने वाले व्यय में भारी वृद्धि के बारे में भी प्रतिकूल टिप्पणी की है। संसद और संसद के बाहर भाजपा नेताओं द्वारा लगाये गए भ्रष्टाचार के आरोपों और घटिया आधारभूत ढांचे संबंधी आरोपों और मीडिया द्वारा चलाए गए प्रतिकूल अभियान को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने खेलों में भाग लेने वाले राष्ट्रों को यह आश्वासन दिया है कि 3–14 अक्तूबर के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए स्टेडियम पूरे हो जाएंगे।

राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के प्रेसीडेंट माइक फेनल घबराकर दिल्ली पहुंचे और एक प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने कहा कि "हम (राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ) किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फेनल ने कहा "भ्रष्टाचार की रिपोर्टों की पूर्ण जांच की जानी चाहिए और कानून के अनुसार उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए।" फेनल ने खेलों तथा आधारभूत ढांचे के विकास संबंधी मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से भी मुलाकात की।

परंतु कहीं कोई सुधार नहीं हुआ। मुख्य स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बिल्कुल सामने एक निर्माणाधीन पैदल पुल टूटकर गिर गया, जिसमें 27 लोग घायल हो गये और भारोत्तोलन क्षेत्र में एक फाल्स सीलिंग टूट गई। स्थिति से निपटने के लिए सेना की मदद ली गई।

इन सब बातों से उच्चतम न्यायालय ने उत्तेजित होकर टिप्पणी की कि राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और वह "व्याप्त भ्रष्टाचार" के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं रख सकता और उसने भारत सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम के लिए उसकी तैयारियों के लिए आलोचना की। खेलों संबंधी सभी ठेकों के लिए टेंडर मंगाने की प्रक्रिया में धांधली और अनियमितताओं के अनेक आरोप है, जिनकी जांच की जानी चाहिए। श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरूण जेटली, श्री कीर्ति आजाद, श्री नवजोत सिंह सिद्धू तथा श्री अनुराग ठाकुर सहित वरिष्ठ भाजपा नेता संसद के दोनों सदनों में ये मामले उठाते रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता, श्री विजय कुमार मल्होत्रा, पार्टी के महासचिव, श्री विजय गोयल एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा खेल प्रकोष्ठ संयोजक, श्री महिन्दर लाल ने दिल्ली में खेलों संबंधी घोटालों के विरूद्ध अभियान चलाया।

भाजपा के इन सभी नेताओं तथा सचिव श्री किरीट सोमैया ने खेलों में कुप्रबंधन के बारे में तथ्य एकत्रित करने के लिए अथक प्रयास किए और ''राष्ट्रमंडल खेलों में लूट संबंधी भाजपा की प्रथम सूचना रिपोर्ट'' तैयार की। इसके साथ उन्होंने एक भारी भरकम अनुबंध भी तैयार किया, जिसमें सरकारी एजेंसियों और खेल निकायों द्वारा कर–दाताओं के धन की पूर्णतया बरबादी के प्रति दिखाई गई बेदर्दी

एवं पूर्ण उदासीनता उजागर होती है। इसके परिणामस्वरूप खेल बजट जो शुरू में 2000 करोड़ रूपये का था बढ़कर 70,000 करोड़ रूपये की भारी भरकम राशि का हो गया।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूर्व सीएजी, श्री बी.के. शुंगलु की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है। अनेक सरकारी एजेंसियों को जैसे प्रवर्तन निदेशालय, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सीएजी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना, तथा अन्य एजेंसियां, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा कदाचारों आदि को विशिष्ट आरोपों की अपनी–अपनी जांच करने के लिए इसमें शामिल किया गया है।

अब शीला दीक्षित, सुरेश कलमाड़ी तथा अन्य लोगों द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में खुले में कीचड़ उछाला जा रहा है, जहां कलमाड़ी न केवल राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के 1620 करोड़ रूपये के बजट की जांच की मांग कर रहे हैं बल्कि दिल्ली सरकार के 16,000 करोड़ रूपये के बजट की जांच की भी मांग कर रहे हैं। भाजपा की यह पुरजोर मांग है कि ये सभी जांच तथा छानबीन शीघ्रातिशीघ्र पूरी की जानी चाहिए, जिससे किसी तर्क संगत निर्णय पर पहुंचा जा सके ताकि दोषियों को बिना विलंब किए दंडित किया जा सके।

इस कार्य में अनेक एजेंसियों के शामिल होने की बात को ध्यान में रखते हुए हम मांग करते हैं कि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समन्वय समिति गठित की जाए ताकि घोटालों का पता लगाने के लिए प्रभावी और समेकित प्रयास सुनिश्चित किये जा सके। इन सभी प्रकार की जांचों के माध्यम से यह पता लगाया जाना चाहिए कि विभिन्न सौदों में कितना और किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ और इनमें शामिल एजेंसियों ने क्या भूमिका अदा की ताकि दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जा सके। भाजपा सभी जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग प्रदान करेगी और भ्रष्टाचार और धांधली के सभी आरोपों की निष्पक्ष एवं अर्थपूर्ण जांच करने में इसके नेताओं द्वारा एकत्रित सूचना उपलब्ध कराएगी।

परन्तु इसके साथ–साथ मैं यह महसूस करता हूं कि शीघ्र ही उन लोगों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाये, जिन्होंने इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की और जिन्होंने परियोजना प्रतिवेदनों में गंभीर त्रुटियों को अनदेखा करते हुए समय–समय पर निधियों का आवंटन किया और जो इन परियोजनाओं की अनुचित भारी लागत वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अब समय आ गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में लूट में शामिल भागीदारों तथा इस गड़बड़ी को अनदेखा करके उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने वालों के बीच सांठ–गांठ का पर्दाफाश किया जाए। भारत के लोगों को यह जानने का पूरा संवैधानिक हक है कि इस राष्ट्रीय बदनामी के लिए असली अपराधी कौन है।

सच्चाई तभी समाने आएगी जब एक खुली विस्तृत जांच कराई जाए और वह एक संयुक्त संसदीय जांच के माध्यम से ही हो सकता है। भाजपा मांग करती है कि राष्ट्रमंडल खेलों में करोड़ों की लूट संबंधी इस महत्वपूर्ण घोटाले की जांच शीघ्रातिशीघ्र एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करके कराई जाए।

प्रस्तावित संयुक्त संसदीय समिति के निर्देश पदों में अन्य बातों के साथ–साथ एक ऐसे त्रुटिविहीन तंत्र का बनाया जाना शामिल होना चाहिए, जिससे भविष्य में भ्रष्टाचार तथा घोटाला मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम आयोजित करने में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

कांग्रेस बताए

एण्डरसन को भारत से भगाने में क्या सौदेबाजी हुई थी : नितिन गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 26 अगस्त 2010 को भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य

भोपाल गैस त्रासदी के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को न तो न्याय मिला है और न ही राहत। गत सात जून, 2010 को आए न्यायालय के निर्णय ने भी घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। विडम्बना यह है कि इस नरसंहार के दोषी या तो विदेशों में कानून की पकड़ से बाहर हैं या देश के भीतर भी खुलेआम घूम रहे हैं। इन दोषियों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों का बाल भी बांका नहीं हुआ हैं। नतीजा यह है कि 26 वर्ष पहले भोपाल में लगे घाव अभी भी रिस रहे हैं।

भोपाल गैस त्रासदी और तत्पश्चात् के घटनाक्रम के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा एक–दूसरे के पाले में गेंद फेंकने से एक असंवेदनशील प्रशासन और उत्तरदायित्वविहीन राजनीतिक नेतृत्व का चेहरा सामने आता है। इसी संस्कृति को कांग्रेसी सरकारों ने पूरी तरह से पाला–पोसा है, जिसका परिणाम पूरे देश को, विशेष रूप से भोपाल को भुगतना पड़ा है। 26 वर्ष, 20 हजार से अधिक मौतें और पांच लाख से ज्यादा लोगों के इस त्रासदी का शिकार होने के बावजूद आज तक किसी की जवाबदेही तय न हो पाना – भोपाल के गैस पीड़ितों को न्याय और राहत मिलने में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।

कांग्रेसी सरकारों और नेतृत्व को यह बताना ही पड़ेगा कि हत्यारी यूनियन कार्बाइड के सी.ई.ओ. वारेन एण्डरसन को भारत से भगाने में क्या सौदेबाजी हुई? और किसने की? राज्यसभा में इस पर हुई बहस में श्री अर्जुन सिंह से उम्मीद थी कि वे अभी तक अनुत्तरित सवालों का जवाब देंगे और रहस्यों पर से ही पर्दा उठाएंगे! मगर उन्होंने लोगों के विश्वास से एक बार फिर छल किया। पहला छल उन्होंने त्रासदी के समय मुख्यमंत्री रहते किया तो अब असली दोषियों के चेहरे से नकाब न उठाकर किया! उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं या राजनीति में हाशिये पर पहुंचकर भी कुछ पाने की लालसा उनको पूरा सच सामने लाने से रोक रही हो। मगर उनको मध्यप्रदेश, विशेषकर भोपाल के उन लोगों के प्रति अपना कुछ दायित्व निभाना चाहिए था जिन्होंने उन्हें एक मुख्यमंत्री और एक केन्द्रीय मंत्री बनाने में सहयोग किया। क्या कांग्रेसी नेताओं की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए बीस हजार से ज्यादा लोगों की मौत तथा पांच लाख से अधिक शिकार हुए लोगों की कीमत कम है? सत्य को दबाकर कांग्रेस इतिहास नहीं बदल सकती। भोपाल पर एक 'श्वेत पत्र' जारी करने की जरूरत है जो वर्तमान पीढ़ी

को सच बता सके!

कांग्रेसी नेतृत्व भोपाल गैस त्रासदी से हुए नरसंहार के पाप से बच नहीं सकता। अपने दोषों को छिपाने के उद्देश्य से कांग्रेसी सरकार यूनियन कार्बाइड के सी.ई.ओ. वारेन एण्डरसन को वापस भारत लाने की घोषणा कर रही है। हम ऐसे किसी भी प्रयास में सरकार को पूरा सहयोग करेंगे मगर क्या वर्तमान केन्द्र सरकार अमेरिका से यह कहने का साहस कर पाएगी? प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह अपनी पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने यह मुद्दा नहीं उठा पाये! अब फिर से मौका आ रहा है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रस्तावित भारत यात्रा के समय दृढ़ता से यह मुद्दा उठायें और वे भोपाल के दोषियों को भारत को सौंपने में सहयोग करें।

दोषियों को दण्ड और पीड़ितों को न्याय व राहत–किसी भी सरकार की नीति का आधार होना चाहिए। अतीत की तरह केन्द्र की वर्तमान कांग्रेसी सरकार इस कसौटी पर असफल सिद्ध हुई है। कांग्रेस सरकारों की इस सम्बन्ध में लचर और संदेहास्पद भूमिका के चलते देशवासियों को यह भरोसा नहीं है कि वर्तमान सरकार इस सम्बन्ध में सही काम कर पाएगी। अतः मेरी मांग है कि इस प्रकरण की निगरानी और समीक्षा नियमित एवं सुचारू रूप से करने के उद्देश्य से एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। साथ ही भोपाल के गैस पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं राहत दिलाने के उद्देश्य से सारे केसों को एक विशेष अदालत गठित करके तुरंत निपटाया जाए।

केन्द्र सरकार की बाधाओं के बावजूद मध्यप्रदेश की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग तथा गैस पीड़ितों के पुनर्वास और चिकित्सा सम्बन्धी प्रयास प्रशंसनीय हैं। भाजपा सरकार तथा प्रदेश में भाजपा के विधायकों तथा सांसदों ने केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में धरना–प्रदर्शन भी किए हैं। भाजपा संगठन और सरकार के प्रयास तब तक जारी रहेंगे जब तक एक–एक गैस पीड़ित का पुनर्वास, चिकित्सा और राहत नहीं मिल पाती।

भोपाल अतीत का एक दुखदायी अध्याय है, परन्तु यह वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी भी है। इसलिए भोपाल गैस त्रासदी और उसके पश्चात् की स्थिति से निपटने में हमारे प्रयास आपदा प्रबंधन के सर्वोत्तम मॉडल बनना चाहिए।

मैं सरकारों, सभी राजनीतिक दलों, सभी स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं से अपील करता हूं कि वे भोपाल त्रासदी की चुनौती को एक ऐसे अवसर में बदलने में सहयोग करें जो हमारे राष्ट्रीय संकल्प और जिजीविषा का प्रकटीकरण हो कि आपदा जैसी भी हो, हम उससे बेहतर ढंग से निपट सकते हैं।

संप्रग शासन में घोटाला

प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें : नितिन गडकरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 18 नवम्बर, 2010 को प्रेस वार्ता में वक्तव्य जारी कर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से प्रश्न किया कि वे राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े

प्र. 1 प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी.एस लाली के विरूद्ध अभी तक कोई आपराधिक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, जिन्होंने वित्त विभाग की आपत्तियों को अनदेखा किया और राष्ट्रीयमंडल खेलों के 246 करोड़ रूपये के प्रसारण अधिकार, एक ऐसी अवैध कम्पनी को दिये जिसने फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया और जिसके पास कोई सेवाकर नम्बर नहीं था ?

क्या श्री लाली को, जिन्होंने खेल समाप्त होने से पूर्व ही संविदा फीस की 80 प्रतिशत राशि का तुरन्त भुगतान कर दिया, उनके उच्च सम्बंधों के कारण –संरक्षण दिया जा रहा है? यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि संप्रग सरकार ने अभी तक आयकर विभाग के इन निष्कर्षों पर पूर्णतया चुप्पी साधी हुई है कि प्रसारण सौदा इंग्लैड की एक कम जानी पहचानी कम्पनी, एसआई एस लाइव (SIS Live) ने हासिल किया था।

जो बिड सम्बंधी औपचारिकताओं के पूरा होने के चार महीने बाद अस्तित्व में आई थी।

आयकर विभाग ने 6 अक्तूबर 2010 को एक पत्र भेजा था जिसमें भविष्य में किये जाने वाले सभी भुगतानों पर रोक लगाने के लिये कहा गया था और इसके साथ–साथ एकाटलैंड के रायल बैंक की मुम्बई शाखा में कम्पनी के खाते को जब्त करने के लिए कहा गया था। जब आयकर अधिकारियों ने दिल्ली में एसआईएस लाइव के कार्यालय की छानबीन की तो उन्हें पता चला कि कम्पनी ने कोई खाता नहीं रखा और न ही कोई बिल रखे। आगे छानबीन से यह पता चला कि एसआईएस लाइव ने अनेक शर्तों का उल्लंघन किया। इसने एक अन्य कम्पनी, जूम कम्युनिकेशन (Zoom Communication) को उप–ठेके पर सौंप दिया, जो ओखला में उसी परिसर से अपना कार्यसंचालन करती हुई पाई गई। एसआईएस लाइव अधिकारी 177 करोड़ रूपये के उप–ठेके सम्बंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये थे।

अपनी टिप्पणी में आयकर रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईएस लाइव "राष्ट्रमंडल खेलों सम्बंधी ठेके को पूरा करने के एकमात्र उदेश्य से बनाई गई थी और कर–निर्धारिती के भारत में रहने की कोई संभावना नहीं है।"

प्र. 2 श्री कनिष्क सिंह, जो श्री राहुल गांधी के निकट सहायक हैं, के ईएमएएआर एमजीफ के मलिकों के साथ क्या सम्बंध है जिसने घटिया राष्ट्रमंडल खेल लैटों का निर्माण किया ?

किसके कहने पर दि.वि.प्रा. द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जोन के लिये 750 करोड़ रूपये एवं 827 करोड़ रूपये का वेलआउट पैकेज दिया गया ? क्या आप यह नहीं मानते कि उत्तरदायित्व पूरा न करने के लिए केवल ईएमएएआर एमजीफ बैंक गारंटी की शर्त रखना राहुल गांधी के साथी कनिष्क सिंह और उनके परिवार को बचाने के लिये मात्र दिखावा है।

प्र. 3 क्या आप इस तथ्य से इंकार कर सकते है कि वर्ष 2009–10 Overlays के लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के योजना बजट में 126 करोड़ रूपये के प्रावधान में संशोधन करके उसे 687 करोड़ कर दिया गया जिसमें 557 करोड़ रूपये आयोजन समिति को अग्रिम रूप से दिए गए। कृपया क्या आप कॉमनवेल्थ खेलों के Overlays के लिए किए गए प्रावधानों में इस प्रकार की भारी वृद्धि के औचित्य के बारे में देश को कुछ बता सकते हैं?

प्र. 4 आपके खेल मंत्री ने राज्यसभा में यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं की लागत वृद्धि का कारण यह है कि प्रारंभिक अनुमान अधूरे, कम जानकारी के आधार पर स्वीकृत किए गये थे और राष्ट्रमंडल खेल संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के विभिन्न अनुमानों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया गया था।

प्र. 5 इस खेल कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति को 1669.42 करोड़ रू की अग्रिम राशि की स्वीकृति देने और OVERLAYS (अस्थायी फिटिंग एवं फिक्सचर इत्यादि) के लिए 687 करोड़ रू. की अग्रिम स्वीकृति देने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें से 557 करोड़ रू. वास्तव में दिए गए और टाईमिंग, स्कोरिंग तथा रिजल्ट सिस्टम (TSR) और खेल टाईमिंग उपकरण के लिए अनुमोदित 37 करोड़ रू. में से वास्तव में 81 करोड़ रू. दिए गए?

अब जबकि खेलों से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय से हुई कुल आय कम है तो आप इस भारी अंतर को किस प्रकार पूरा करने जा रहे हैं? विज्ञापनों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है और टिकटों की ब्रिकी से केवल 39.17 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि 375 करोड़ रू. की तयशुदा मूल्य की तुलना में 114.5 करोड़ रू. ही स्पांसरशिप के रूप में प्राप्त हुए और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अधिकारों के दिए जाने से 213.45 करोड़ रू. की तयशुदा मूल्य की तुलना में केवल 137.71 करोड़ रू. वसूल हुए।

प्र. 6 कॉमनवेल्थ खेलों में लोगों की निराशाजनक उपस्थिति और टिकट ब्रिक्री में घपले के लिए आप किसे दोषी ठहराते है? क्या आपको इस तथ्य की जानकारी है कि साढ़े ग्यारह लाख छापी गई टिकटों में से केवल आधी टिकट ही दर्शकों द्वारा खरीदी गई?

मैं समझता हूं कि आपके खेल मंत्री ने आपको यह भी बताया होगा कि 3 अक्टूबर के उद्घाटन और 14 अक्टूबर के समापन के दौरान टिकटों की बिक्री में भारी घपला हुआ है, जिसके बारे में दर्शकों ने यह शिकायत की कि अनेक आसपास की सीटें खाली थी, जबकि अधिकारियों का दावा है कि सभी टिकटें बिक गई है।

उद्घाटन और समापन समारोह के लिए निःशुल्क टिकटों को भारी संख्या में छापने और एक ही सीट के लिए कई टिकटें छापने के लिए आप किसे बलि का बकरा बनाने जा रहे है?

प्र. 7 आपकी सरकार ने यह दावा किया है कि राष्ट्रमंडल परियोजना से संबंधित ठेकेदारों, अधिकारियों और कुछ फर्मों के विरूद्ध उसने कार्यवाही शुरू की है। लेकिन, राष्ट्रमंडल खेल लूट में शामिल राजनैतिक व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कोई कार्रवाई की गई है?

आपके खेल मंत्री के अनुसार, 22 मार्च 2007 से लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता

में मंत्री के समूह की 14 बैठकें हुई और पहले शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में 34 अतिरिक्त बैठकें हुई जिन्होंने 23 जून, 2009 से खेलों तक फिर से बनाए गए मंत्रियों के समूह की अध्यक्षता की थी।

राष्ट्रमंडल खेलों की लूट में उनको मिले हिस्से की छानबीन कौन करेगा? राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में शामिल व्यक्तियों का पर्दाफाश केवल संयुक्त संसदीय समिति के गठन से ही हो पाएगा, जिसके लिए भाजपा संसद में और संसद के बाहर मांग करती आ रही है।

प्र. 8 राष्ट्रमंडल खेल परियोजना के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा आबंटित 300 करोड़ रू. का क्या हुआ जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को सौंपा गया था। इस कार्य पर मुश्किल से कुछ करोड़ ही खर्च होते, जिसमें 7000 वर्ग फीट में निर्माण कार्य होना था और एक एकड़ क्षेत्र का सौंदर्यकरण होना था। यह धनराशि कहां गई ?

प्र. 9 इसी प्रकार निम्नलिखित मामलों में की गई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में राष्ट्र को आपके प्रति उत्तर की प्रतीक्षा है।

क्वींसबैटन रिले, SMAM घोटाला ट्रेडमिल्स स्पांसरशिप, गेम वेबसाइट, टेनिस सरफेस, केटरिंग, मर्कैंडाइजिंग 22,000 स्वयंसेवकों की मान्यता 2,000 से अधिक स्टॉक और हजारों मीडियाकर्मी, खिलाड़ी और प्रतिनिधि, पार्किंग कनॉटप्लेस पुनर्विकास योजना, चांदनी चौक, पहाड़गंज, करोलबाग, शिवाजी स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम।

प्र.10 विवादास्पद 2जी स्पैक्ट्रम निर्धारण मामले में श्री ए. राजा पर मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति देने से आपके द्वारा निर्णय लेने में होने वाले विलंब संबंधी सीधे–सीधे प्रश्न के उत्तर देने से आपको कौन रोक रहा है? आप इस बारे में लोगों को क्यों नहीं बता रहे?

गोवा

सीबीआई का राजनीतिक दुरूपयोग कर रही है कांग्रेस

भाजपा ने संप्रग द्वारा विगत 6 वर्षों में सीबीआई के घोर दुरूपयोग पर आपत्ति व्यक्त की है। संप्रग I तथा II ने (1) कांग्रेस के नेताओं तथा अन्य संप्रग नेताओं के अपराधों पर पर्दा डालने या उन पर लीपापोती करने के लिए (2) प्रतिपक्ष के, विशेषतया भाजपा, सपा और राजग के कमजोर मन के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए और (3) प्रतिपक्ष के उन नेताओं को जो सरकार के दबाव में नहीं आये थे, परेशान करने के लिए सीबीआई का उपयोग किया है।

कांग्रेस नेताओं के अपराधों पर पर्दा डालना या उन पर लीपापोती करना

इस उदाहरण के तहत दो कुख्यात केसों का हवाला दिया जा सकता है :

1. श्री अजीत जोगी के विरूद्ध केस (विधायकों को खरीदना) को सीबीआई का इस्तेमाल करके सुनियोजित रूप में समाप्त किया गया। (Outlook India Website, 27 April, 2010)
2. सीबीआई का दुरूपयोग करके बोफोर्स केस और इटलीवासी क्वात्रोची को भारतीय न्यायालयों के सामने पेश करने में पूर्ण विफलता को अंजाम दिया गया।

(Source : Outlook India 27, April, 2010)

3. दिल्ली के एक न्यायालय ने (23 फरवरी, 2010 को) सीबीआई के पूर्व कांग्रेसी सांसद श्री सज्जन कुमार को गिरफ्तार करने और पेश करने में हुई विफलता की आलोचना की थी। एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, "सीबीआई के प्रभाव की वास्तविकता पर संदेह बना हुआ है... सीबीआई के काम करने का क्या यही तरीका है। सारे गवाह कहां चले गए?"

(Source : www.thehindu.com 24 Feb. 2010)

4. उच्चतम न्यायालय ने श्री जगदीश टाइटलर को 1984 के सिख विरोधी दंगों के केस में क्लीन चिट देने में "केन्द्र के कहने पर कार्य करने" के लिए सीबीआई की आलोचना की थी। सीबीआई की तहकीकात में अनेक खामियां पाई गई, जो स्पष्ट संकेत देती थी कि केन्द्र श्री टाइटलर को राहत देने के लिए सीबीआई को निर्देश दे रहा था। (One India News 2 April, 2009)

प्रतिपक्ष के कमजोर मन वाले नेताओं पर दबाव डालना

1. सुश्री मायावती ने कहा था, "...सीबीआई अवैध रूप से और राजनीतिक दबाव में मेरे विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला चलाए जा रही है।"

(Source : Raj Thackerey News & Info, 23 April, 2010)

किंतु ऐसा होते हुए बजट सत्र अप्रैल 2010 के दौरान कटौती प्रस्ताव पर बहस की पूर्व संध्या को उच्चतम न्यायालय के सामने एक बयान दिया गया, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के उसी केस को हल्का करने की कोशिश की गई। इस प्रकार सीबीआई का दुरूपयोग किया गया।

(Source : Outlook India 27, April, 2010)

जनता दल (यू) के श्री शरद यादव ने भी सरकार द्वारा सीबाआई का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया। (Source: DNA News 28, April, 2010)

पुनः सुश्री मायावती के ताज कॉरिडोर केस में सीबीआई द्वारा मारी गई पलटी सबकी जानकारी में है, जिसे मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था।

(www.outlookindia.com 27 April, 2010)

2. श्री अमर सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले और लोक हित मुकद्दमे में उच्च्तम न्यायालय में प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बन गई है" उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तथा इस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल पैदा हो गए हैं।

(Source: The Indian Express website 11 Feb. 2009)

3. श्री लालू यादव के विरूद्ध केस को नाजुक मोड़ पर लोक अभियोजक बदलते हुए कमजोर किया गया।

श्री यादव को आयकर वभाग की कार्यवाहियों को मिलीभगत से मैनेज करके और सीबीआई का दुरूपयोग करके दोषमुक्त करवाया गया। (Source : Outlook India, 27 April 2010)

सीबीआई ने श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के विरूद्ध अपने स्वयं के निष्कर्षों को रद्दी का पुलिंदा बताया। सीबीआई ने अपने शुरू के तर्कों को नकारते हुए इस प्रक्रिया में बिहार सरकार का विरोध किया।

(Source : hindu.com, tehelka.com, timesofindia.com, dnaindia.com etc.)

4. श्री मुलायम सिंह यादव के आय से अधिक संपत्ति के केस में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को बुरा–भला कहा था। इससे पहले न्यायालय ने आलोचना की थी "सीबीआई केन्द्र के कहने पर कार्य कर रही है"। (Source: ibnlive.in.com : 11 Feb, 2009)

5. संप्रग सरकार ने श्री मुलायम सिंह के विरूद्ध आरोपों को दबा दिया क्योंकि सरकार को समाजवादी पार्टी के सांसदों के समर्थन की जरूरत थी।

प्रतिपक्ष के जिन नेताओं पर सरकार दबाव नहीं डाल सकती उन्हें परेशान किया जाना।

देशभर में पुलिस द्वारा खतरनाक अपराधियों के साथ फर्जी मुठभेड़ के मामले रजिस्टर्ड किये जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उन्हें प्रकाशित किया गया है।

- संप्रग सरकार ने गुजरात में "एन्काउंटर किलिंग" के केस को सीबीआई को सौंपने में असाधारण रूचि ली है हालांकि इससे पहले ही गुजरात पुलिस ने अनेक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्र फाइल कर दिए थे।

- सोहराबुद्दीन पर इससे पहले ही आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया था और उसे 1995 में गिरफ्तार किया गया था तथा पुलिस की रिमांड में दिया गया था। सोहराबुद्दीन के खेतों में एक कुंए से 24 एके–56 राइफलस्–27 हैंड ग्रिनेडस्, 5250 कारतूस और 81 मैंगजीन बरामद हुए थे।

- सोहराबुद्दीन, दाऊद और लतीफ गिरोहों का सहयोगी रहा था।
- अनेक केसों में सोहराबुद्दीन के साथी अर्थात् शरीफ खां (छोटा दाऊद के रूप में ज्ञात) और रसूल पार्टी अपराधी तथा राष्ट्र विरोधी घोषित किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए हैं।
- सोहराबुद्दीन के विरूद्ध विभिन्न राज्यों में अनेक केस लंबित हैं।

राज्य की सीआईडी क्राइम स्थिर गति से कार्य कर रही है और उसने उच्च पुलिस अधिकारियों सहित 13 अभियुक्तों को चार्जशीट कर दिया है।

संप्रग सरकार जो आगे–पीछे कार्य करती है उस पर गैर–सरकारी संगठनों द्वारा दबाव डाला जा रहा है और उनके कार्यकर्ताओं ने सोहराबुद्दीन जैसे राष्ट्र विरोधी तथा अपराधी का मामला हाथ में ले लिया है। राज्य पुलिस द्वारा आरोप पत्र फाइल किए जाने के पश्चात् सीबीआई ने इस मामले में प्रवेश कर लिया है।

इस मामले में गुजरात पुलिस द्वारा विफलता के जिन 4 कारणों की पहचान की गई थी उनको सीबीआई को केस सौंपे जाने की वजह बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के 12 जनवरी, 2010 के आदेश के बाद तथा सीबीआई द्वारा इस केस को हाथ में लेने के पश्चात् भी सीबीआई ने उन चार बिंदुओं पर आज की तारीख तक कोई प्रगति नहीं की है।

क्या यह एक संयोग मात्र ही हो सकता है कि इस मामले में सुपरवाइजरी अधिकारी मिस्टर कंडास्वामी है, जिसकी प्रसिद्धि का यह दावा है कि उसने तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री के कहने पर करूणानिधि को गिरफ्तार किया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।

डीएमके के सत्ता में आने पर उक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई चला गया।

गुजरात के मुख्यमंत्री को दबाने और बदनाम करने के लिए सीबीआई का दुरूपयोग किया जा रहा है। गुजरात राज्य को इसलिए सजा दी जा रही है कि उसने प्रत्येक चुनाव में बार–बार भाजपा को विजयश्री प्रदान की है।

आन्ध्र प्रदेश : हैदराबाद

यूपीए की गलत आर्थिक नीतियां ही भारी मुद्रास्फीति का कारण

भा

जपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कांग्रेसनीत यूपीए सरकार से मांग की है कि केन्द्र तुरंत ही आवश्यक वस्तुओं को वस्तु–विनिमय श्रेणी से बाहर निकाले और इनका वायदा व्यापार बंद करे क्योंकि इससे सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों को भारी हेराफरी करने का मौका मिलता है जिसकी आम आदमी और गरीबों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पार्टी की बागडोर संभालने के बाद श्री गडकरी ने पहली बार हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने 6 जून को एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा– ''सरकार कम से कम जो एक काम कर सकती है, वह यह है कि वह आवश्यकता वस्तुओं को वस्तु–विनिमय श्रेणी से बाहर निकाल सकती है। मैं यह मांग पिछले चार महीनों से करता आ रहा हूं। प्रधानमंत्री भी इससे सहमत हैं, परन्तु अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है।''यूपीए सरकार की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए की गलत आर्थिक नीतियों और खराब प्रशासन ही आज आर्थिक संकट और भारी मुद्रास्फीति का कारण है।''

आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात जोरदार ढंग से पेश की और उनके सामने आलू उत्पादन करने वाले किसानों का उदाहरण पेश किया जो सिद्ध करता है कि किस प्रकार से वस्तु–विनिमय हेराफेरी और सट्टेबाजी का स्रोत बन गया है। 2009 में, वस्तु–विनिमय के अन्तर्गत आलू की कुल बिक्री केवल 40 लाख टन थी परन्तु वास्तविक सुपुर्दगी 7000 टन ही हुई। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही हुआ कि इस व्यापार में 99.82 प्रतिशत केवल कागजों पर रह कर सट्टेबाजी में चला गया। इस विनिमय की कुल बिक्री 10,88,224 करोड़ रूपए हुई और सुपुर्दगी मात्र 3591 करोड़ हुई। इस प्रकार 10,84,633 करोड़ रूपए की शेष राशि सट्टेबाजी में चली गई। जहां एक तरफ आलू उत्पादक किसानों को 2 रूपए से 4 रूपए प्रति किलोग्राम का भाव दिया जाता है, वही हम देखते हैं कि पिछले वर्ष अक्तूबर–नवम्बर में आलू की खुदरा कीमत मेट्रो शहरों में 20 से 24 रूपए प्रति किलोग्राम थी। इसलिए यूपीए सरकार को जवाब देना होगा कि इससे किसको लाभ पहुंचा? क्या यह कार्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नहीं थीं?

श्री गडकरी ने इस स्थिति के लिए कांग्रेस–नीत सरकार को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि 2004 में आवश्यक वस्तुओं को वायदा/अगाऊ बाजार में बदल दिया गया था। कृत्रिम बिक्री ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया।

श्री गडकरी ने केन्द्रीय सरकार द्वारा 58,000 करोड़ रूपए के अनाजों के सड़ने की बात को स्वीकार

करने का उल्लेख करते हुए इस घोटाले की जांच की मांग भी की। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़ी हुई गेहूं को 3 रूपए प्रति किलो ग्राम की नाम मात्र मूल्य पर शराब–निर्माताओं की लॉबी को बेचा गया, जबकि हम देख रहे हैं कि गरीब लोग भूख के मारे मरे जा रहे हैं।

श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार का दूसरी बार सत्ता संभालने का शासन एकदम विफल रहा है। इस शासनकाल में हर मोर्चे पर सरकार का हताशापूर्ण प्रदर्शन दिखाई पड़ा है। अगर उसकी इस दौरान कोई उपलब्धि रही है तो वह यही रही कि इस काल में निरंतर कीमतें बढ़ती रहीं, मुद्रास्फीति का प्रसार बढ़ता गया, आम आदमी का कभी खत्म न होने वाला संकट बना रहा, किसानों की आत्महत्याओं में वृद्धि होती रही और शहरों तथा गांवों में बेरोजगारी अपने पांव पसारती रही।

उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने 100 दिनों में मंहगाई के मुद्दे का समाधान निकालने का वायदा किया परन्तु हुआ यह है कि अनेकानेक वस्तुओं की कीमतें 100 प्रतिशत तक बढ़ गईं। आज मुद्रास्फीति 17–20 प्रतिशत के बीच फैली हुई है। उधर कृषि का हाल भी नकारात्मक है।

24 मई 2010 को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की समाप्ति पर स्वयं स्वीकारा है कि –

- ''निरंतर बढ़ती कीमतें गहरी चिंता का विषय है। सरकार मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है ताकि आम आदमी संकट से बाहर निकले।''
- किन्तु, उन्होंने बढ़ती गरीबी, गरीबों–अमीरों के बीच बढ़ती असमानता की खाई और किसानों की आत्महत्याओं की बात तक नहीं की।

  कांग्रेस अध्यक्षा और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी तथा डॉ. मनमोहन सिंह ने 29 मई को यूपीए का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जिसमें स्वीकारा गया है कि–
- ''आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या कीमतों पर दबाव की है।'' डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि हम बहुत ध्यान से इस स्थिति पर नजर रखते रहेंगे और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए जो भी सुधारात्मक उपाए करने होंगे, उन्हें करेंगे।

  उन्होंने कुछ चुनिंदा वस्तुओं के निर्यात और खाद्यान्नों के वायदा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही।

  श्री गडकरी ने केन्द्र सरकार को बेनकाब करते हुए कहा कि उसने 2009–10 में 7.4 जीडीपी वृद्धि का दावा किया है। विडम्बना है कि इसी अवधि में कृषि विकास मात्र 0.2 प्रतिशत रहा है। उधर बिजली, उर्वरक, बीजों और डीजल आदि की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है।
- आज देश के सामने जल सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। कांग्रेस सरकार ने भाजपा–एनडीए सरकार की नदियों को जोड़ने वाली परियोजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है।
- दक्षिण में, जल और नदियों की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है।
- दक्षिण भारत नदीग्रिड, महानदी, गोदावारी, कृष्णा, कावेरी और पेनार नदियों को आपस में जोड़ने के काम पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है।
- बड़े/छोटे बांधों के निर्माण और अन्य सिंचाई योजनाओं पर काम की मांग भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है।
- भारत में कृषि विकास 0.2 प्रति है जबकि गुजरात में कृषि विकास 14 प्रतिशत हुआ है। आंध्र प्रदेश

सरकार को गुजरात से सबक सीखना चाहिए।

- कृषि बुनियादी ढांचे को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा विकास के लाभों को आम आदमी तक पहुंचना चाहिए।

आंध्र सरकार की विफलता

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने भी दूसरी शासनावधि का प्रथम वर्ष पूरा किया है। इस सरकार की भी सभी मोर्चों पर संकटग्रस्त तस्वीर सामने नजर आती है। नक्सलवाद फैल रहा है।

सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का राजनैतिक नेतृत्व सभी प्रमुख समस्याओं पर बुरी तरह से बंटा दिखाई पड़ता है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनेकों कल्याणकारी योजनाएं वापस ले रही है जैसे फीस की प्रतिपूर्ति, बीसी, इबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली स्कालरशिप आदि। आईआईटी में ग्राम–आधारित विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत सीटों को भी वापस लिया जा रहा है। आरोग्य श्री, इंदिरा आवास योजना, राजीव गृह कल्प तथा पेंशन, महिला एसएचजी की पवाला वद्दी के लिए धन उपलब्ध नहीं है।

भाजपा मांग करती है:

- कृषि–अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाए।
- कृषि विकास और कृषि बुनियादी ढांचे के लिए समुचित धन की व्यवस्था की जाए।
- जल और नदी परियोजनाओं के काम को युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।
- खाद्यान्नों और हार्टिकल्चर स्टोरेज का समुचित प्रबंध होना चाहिए।
- अगले 25 वर्षों के लिए पूर्णस्टोरेज योजना तैयार की जाए।
- किसानों के लिए स्टोरेज स्वामित्व की व्यवस्था हो–
- जिसमें 50 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी दी जाए।
- 45 प्रतिशत वित्तीय पोषण 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर की जाए।
- किसानों की ओर से 5 प्रतिशत के अंशदान की व्यवस्था र

भाजपा द्वारा प्रस्तुत पत्र व ज्ञापन

भारतीय जनता पार्टी ने समय-समय पर जन-समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल और प्रधानमंत्री को पत्र व ज्ञापन सौंपकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। हम यहाँ सम्पादित अंश प्रकाशित कर रहे हैं।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्या समाधान के लिए भाजपा अध्यक्ष का प्रधानमंत्री को पत्र

6 जुलाई 2010 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पत्र लिखा। इस पत्र के मूल पाठ का भावानुवाद नीचे प्रस्तुत है :

fi; Mk- flg]

fo"k; % fcuk jd d Hkr io lfudk dh f'kdk;rk dk lekèkku

हमारे देशवासियों में भूतपूर्व सैनिकों का बहुत अधिक सम्मान है। उनकी बहादुरी की सेवाओं के कारण निश्चित ही उनका स्थान विशेष है। वे अलग प्रकार की विशेष वर्ग के सेवा–निवृत्त लोग हैं। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 14 का भलीभांति 'समुचित' वर्गीकरण करें तो भूतपूर्व सैनिकों से बढ़कर किसी और को ऊपर नहीं रखा जा सकता है। वे सचमुच बेहतर सम्मान के अधिकारी हैं।

न जाने किन कारणों से यूपीए सरकार ने उनकी वास्तविक शिकायतों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया है। देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्त्तव्य बनता है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते आपको स्मरण कराऊं कि आपकी सरकार को चाहिए कि वह भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के प्रति अपनी उपेक्षा और उदासीनता को त्याग दें।

यहां यह स्मरण करना उचित होगा कि 1962 में हमारी सीमा पर चीनी आक्रमण के दौरान हमारे

राष्ट्र को भारी राजनैतिक, क्षेत्रीय, मैटिरियल एवं जन–हानि भी सहनी पड़ी थी। उस पराजय का एक मात्र कारण यही था कि तत्कालीन सरकार और तत्कालीन शिखर राजनैतिक नेतृत्व ने रक्षा मामलों के प्रति उदासीन भाव रखा जिसने देश के सैनिकों के मनोबल को बुरी तरह से आघात पहुंचाया।

देश को 1962 जैसी स्थिति का फिर से (हमारे सशस्त्र बलों की उपेक्षा) सामना न करना पड़े, मैं आपसे भूतपूर्व सैनिकों की समस्या का समाधान करने के लिए आपको स्मरण कराना चाहता हूं। बिना किसी भेदभाव और बिना किसी रैंक'' के पूरी निष्ठापूर्वक इसका समाधान हो।

भूतपूर्व सैनिकों की वास्तविक एवं न्याययुक्त मांगों का विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

(१) वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी)

संसद के अंदर और बाहर वायदों और विभिन्न वक्तव्यों के बावजूद यह समस्या अभी तक भी सही स्वरूप में हल नहीं हो पाई है। भूतपूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति की तारीख और वर्ष के कारण उनकी पेंशन में असमानता आज तक बनी हुई है। इस सम्बंध में छठे वेतन आयोग ने कुछ नहीं किया है।

(२) रैंक वेतन पर ८ मार्च २०१० का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट

माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया ने 8 मार्च 2010 को चौथे वेतन आयोग के अवार्ड के संदर्भ में एक जजमेंट दिया कि सशस्त्र बलों के सैनिकों का रैंक वेतन संशोधित वेतनमानों के अतिरिक्त होना चाहिए। सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों की गलत व्याख्या किए जाने के कारण इस एवार्ड का कार्यान्वयन नहीं किया। किन्तु, जब सुप्रीम कार्ट जजमेंट ने इस विसंगति को ठीक किया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का शालीनतापूर्वक पालन करने की बजाए सुप्रीम कोर्ट में ''मामले को फिर से सुनवाई करने और आदेश संशोधित करने'' का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। कम से कम कहा जाए तो भी यही कहा जाएगा कि यह तो सरकार के भूतपूर्व सैनिकों के प्रति घोर अमैत्रीपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करता है। सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि वह इस आवेदन को वापस ले और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का कार्यान्वयन करे।

(३) रक्षा बल कार्मिकों की सेवाअवधि

वर्तमान रक्षा बल कार्मिक, विशेष रूप से आफिसर रैंक से नीचे के कार्मिक (पीबीओआर) बहुत पहले रिटायर कर दिए जाते हैं। इससे उन्हें ऐसे समय में बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है जब कि उनके परिवारों की जिम्मेदारियां उनके अपने बढ़ते बच्चों के कारण बढ़ जाती हैं। रक्षा कर्मिको की अन्य सुरक्षा सेवाओं में उनके समायोजन से इस समस्या का हल हो सकता है और इससे रक्षा बल कार्मिको को 60 वर्ष तक सेवा करने का अवसर मिलता है।

(४) भूतपूर्व सैनिकों के लिए सांविधिक आयोग की स्थापना

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह वास्तविक संगठनात्मक आवश्यकता है। रक्षा बलों के लिए एक अलग वेतन आयोग से कई विसंगतियां दूर हो सकती है।

उपर्युक्त कथन को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों पर विचार करें और इनका शीघ्रातिशीघ्र समाधान करें। कृपया इस असंतोष को दूर कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि यह सेवारत सैनिकों में फैल जाए और इससे उनका मनोबल भी नीचे गिर जाए।

सादर

भवदीय
(नितिन गडकरी)

भाजपा अध्यक्ष का प्रधानमंत्री को पत्र

अनियमित मानसून के कारण बाढ़/सूखा पीडितों में अनाज का मुफ्त वितरण हो

25 सितम्बर, 2010

fi; Mk- euekgu flg th
Hkkjr d ekuuh; iekkue=h

नमस्कार,

मैं आपका ध्यान देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण आई तबाही की ओर दिलाना चाहूंगा।

नदियों के आप्लावन से उत्पन्न असामान्य मानसून वर्षा ने व्यापक स्तर पर विनाशलीला रच डाली है। बहुत से लोग काल के गाल में चले गए, फसलें नष्ट हो गईं, सड़कें पानी में डूब गई और हजारों गांव के रास्ते कट कर आवागमन से अलग हो गए तथा हजारों परिवार बाढ़ की गिरफ्त में फंस गए।

बाढ़ की स्थिति उत्तराखंड, पूर्वी बिहार और उत्तरी उत्तर प्रदेश में बिगड़ती चली जा रही है। दिल्ली के अनेकों निचले इलाके घुटनों तक पानी से भरे पड़े हैं। उत्तराखंड बुरी तरह से प्रभावित हुआ है जहां बांधों पर वर्षा का जल खतरनाक स्थिति तक पहुंच कर ऊपर से बह रहा है तथा टेहरी बांध को खतरा है। नेपाल में भारी वर्षा से बिहार की कुछ नदियों के तटबंध टूट गए हैं और इन राज्यों में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की राज्य सरकारें अपने सीमित साधनों से इस कठिन स्थिति का सामना करने के लिए कमर कसे हुए है और राहत तथा पुनर्वास का कुछ काम शुरू हो चुका है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही, असामान्य रूप से अनिश्चित मानसून के कारण बहुत से क्षेत्रों को औपचारिक रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र भी घोषित किया गया है।

माननीय महोदय, आपको स्मरण होगा कि 12 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा था कि वह भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज के सड़ने की बजाय लोगों में इस अनाज का मुत वितरण करे। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने कहा था कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेगी। मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि बाढ़/सूखा पीड़ित राज्यों के एफसीआई गोदामों में पड़े अनाज को मुत वितरण के लिए उन राज्यों वाले अपने–अपने सार्वजनिक वितरण और अन्य व्यवस्था के माध्यम से बाढ़/सूखा पीड़ित लोगों में बांटा जाए, जिसमें उजड़े लोगों को तथा फसल में बर्बाद हुए किसानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। मुझे मालूम हुआ है कि सरकार के पास 605 लाख टन अनाज पड़ा है जबकि उसकी अधिक से अधिक भण्डारण क्षमता 425 लाख टन है। इस प्रकार 180 लाख टन अनाज खुले गोदामों में पड़ा और सड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आप मेरा यह सुझाव मानेंगे और बाढ़/सूखा पीड़ित लोगों को मुत वितरण के लिए अनाज उपलब्ध कराएंगे।

सादर

भवदीय
(नितिन गडकरी)

भाजपा अध्यक्ष का प्रधानमंत्री को पत्र

वक्फ संपत्तियों की आय से मुसलमानों का विकास हो

दिनांक 30 जुलाई 2010

vknj.kh; Mk- euekgu flag th]

विषय : वक्फ संपत्तियों से गैर–कानूनी अतिक्रमण को हटाना

महोदय,

मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और यह है देशभर में वक्फ संपत्तियों पर गैर–कानूनी अतिक्रमण और उनका दुरूपयोग। एक जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न प्रदेशों और संघ शासित प्रदेशों में लगभग 5 लाख रजिस्टर्ड वक्फ मौजूद है। पूरे देश में वक्फ संपत्ति के अंतर्गत तकरीबन 6 लाख एकड़ का क्षेत्रफल आता है, जिसकी सरकारी कीमत आज से 50 साल पहले तकरीबन 8 हजार करोड़ रूपये आंकी गई थी। शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्ति शहरों के बीच में स्थित है, जिसकी वर्तमान कीमत कागजी व सरकारी कीमतों से कहीं अधिक है। सच्चर कमेटी ने वक्फ संपत्ति की कीमत 1.20 लाख करोड़ रूपए आंकी है और सुझाया है कि अगर इन संपत्तियों को प्रभावशाही तरीकों से बाजार का रूख देखकर इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 12 हजार करोड़ रूपए की सालाना आमदनी हो सकती है।

यह धनराशि भारतीय मुस्लिम समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उपयोगी हो सकती थी परन्तु ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करने वाले नकली सेकुलरवादी राजनीतिक दलों के नेताओं और कुछ अन्य तत्वों ने गैर–कानूनी और असंवैधानिक तरीकों से इन संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है।

सर्वविदित है मुस्लिम परम्परा में यदि कोई अनुयायी अपनी कमाई या प्राप्त संपत्ति का एक हिस्सा सेवा या कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है तो यह एक पवित्र काम समझा जाता है। इसी को वक्फ कहते हैं। दान की गई संपत्ति से हाने वाले लाभ का निर्धारित उद्देश्य है कि गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जाये।

जैसाकि मैंने उल्लेख किया कि मुस्लिम समाज के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी इससे किये जा सकते हैं–

- मुस्लिम समाज के युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग, मेडिकल, आई.टी.आई., प्रबंधन शिक्षा देने वाले संस्थान खोले जा सकते हैं।
- शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, खेल की सुविधाओं इत्यादि का रख–रखाव करना और इसको बढ़ावा देना। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति देना।
- इन्हीं वक्फ के माध्यम से मुस्लिम युवाओं को आईएएस जैसी सेवाओं तथा प्रदेशीय राजकीय सेवाओं की परीक्षा हेतु कोचिंग करवाना।
- सामुदायिक उपयोग के लिए मुसाफिरखाना और विवाह भवन का निर्माण कराना।

- मस्जिदों, दरगाहों और कब्रगाहों का रख–रखाव और वक्फ संपत्तियों की देखभाल।
- वक्फ की सम्पत्तियों को रेंट कंट्रोल एक्ट से मुक्त करा कर आय बढ़ाई जा सकती है।
- गरीब विधवाओं को वित्तीय सहायता के साथ–साथ रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना जैसे– बड़े शहरों में रेडीमेड कपड़ों की कटाई व सिलाई की ट्रेनिंग दिलवाकर बड़े ब्रांड के रेडीमेड कपड़ों की उपरोक्त मुस्लिम महिलाओं से ठेके पर सिलाई आदि कराना। गरीब और शारीरिक रूप से विकलांगों की मदद, गरीब लड़कियों की शादी कराना और तलाकशुदा महिलाओं की देखभाल।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुअज्जिम को वेतन देना।

इस संदर्भ में आपसे मेरा अनुरोध है कि देशभर में उन सभी वक्फ संपत्तियों जिन पर अतिक्रमण किया जा चुका है, से कब्जों को तत्काल समाप्त करने की दिशा मे प्रभावी कदम उठाएं ताकि इस राशि का सदुपयोग उपरोक्त उद्देश्यों के लिए करना संभव हो सके। मुस्लिम समाज को आज इसकी आवश्यकता है।

भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार के कदम शीघ्रातिशीघ्र उठाने का आग्रह मैंने सम्बन्धित मुख्यमंत्रियों से किया है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार भी इस दिशा में यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठा कर अपना दायित्व निभाएगी।

इन अपेक्षाओं के साथ,

आपका स्नेहाकांक्षी
नितिन गडकरी

महंगाई के मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन

आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 जनवरी, 2010 को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में तत्काल कदम उठाने की मांग की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं को आश्वासन दिया कि वे महंगाई कम करने की दिशा में हर संभव कदम उठाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अनंत कुमार, श्री गोपीनाथ मुंडे एवं श्री एस.एस. अहलूवालिया शामिल थे।

सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर भाजपा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का दुरुपयोग किए जाने को लेकर 7 मई, 2010 को महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा।

भाजपा का प्रधानमंत्री को ज्ञापन : कर्नाटक राज्यपाल को वापस बुलाएं प्रधानमंत्री

'कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने' के मुद्दे पर भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने अक्तूबर 13, 2010 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि गत कुछ सप्ताहों में घटित घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्यपाल के संवैधानिक पद पर अपनी नियुक्ति के बावजूद, श्री भारद्वाज अपने राजनीतिक अतीत से राजनीतिक रूप से अपने–आप को दूर करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपने उच्च संवैधानिक पद के लिये बिल्कुल योग्य नहीं है। वह संविधानेतर कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए राज्यपाल हंसराज भारद्वाज को वापस बुलाया जाये। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू शामिल थे।

काश्मीर पर भाजपा का प्रधानमंत्री को ज्ञापन

'काश्मीर में भारत की प्रभुसत्ता कमजोर नहीं होने देंगे' इसे लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने 6 सितम्बर, 2010 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता श्री एस.एस. अहलूवालिया शामिल थे।

भाजपा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

10 करोड़ हस्ताक्षर सौंपकर भाजपा ने किया महंगाई का विरोध

बेलगाम महंगाई को काबू करने के लिए 29 जुलाई, 2010 को भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन व देशभर से 10 करोड़ लोगों के महंगाई के विरूद्ध हस्ताक्षर सौंपकर उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। हम यहां ज्ञापन का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैंः-

lok e]
egkefge jk"Vªifr] Hkkjr
jk"Vªifr Hkou]
ubZ fnYyh

fo"k; % eY;ksa esa gkus okyh fujarj of) dks fo:) vke vkneh dh jk"V0;kih fpark] lalx ljdkj dh ?kksj foQyrk dk mtkxj djus rFkk vke vkneh dh rdyhQksa dks nwj djus ds fy, rRdky dkjZokbZ gsrq Kkiu

आदरणीया महोदया,

भारत के करोड़ों आम लोगों की ओर से कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार की देश में रोजमर्रा के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में घोर विफलता के कारण जनसाधारण को जो तकलीफें और परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी वेदना को आपके सामने उठाने के लिए प्रस्तुत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रत्येक कोने से जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा कारनिकोबार तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक शामिल हैं, लोगों से करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं। लोगों की व्यथा और दयनीय स्थिति को व्यक्त करने के लिए यह ज्ञापन आपको प्रस्तुत किया जा रहा है – वह दयनीय स्थिति, जो संप्रग सरकार की जन–विरोधी गरीब–विरोधी, किसान विरोधी तथा मध्यम वर्ग विरोधी नीतियों और गलत आर्थिक नीतियों के कारण करोड़ों लोगों की व्यथा के प्रति संवेदनहीनता, भावशून्यता तथा निर्ममता भरे रवैये के कारण पैदा हुई है। दैनिक प्रयोग की सारी वस्तुओं – यथा दाल, सब्जी, चीनी, कुकिंग गैस,

कैरोसिन, पैट्रोल, डीज़ल, बिजली, पानी आदि के मूल्य कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे प्रत्येक गृहस्थी का बजट चरमरा गया है और जनसाधारण पर भारी बोझ आ पड़ा है।

संप्रग के आश्वासन और उसकी घोर असंवेदना

स्मरणीय है कि लोकसभा चुनाव – 2009 के दौरान कांग्रेस – संप्रग ने अपने चुनावी घोषणापत्र तथा चुनावी अभियान के दौरान वायदा किया गया था कि "अगले 100 दिनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए जाएंगे।" यह देखकर घोर निराशा हुई कि संप्रग सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन पूर्णतः लापरवाही भरा रहा है। सरकार का कहीं पर भी नियंत्रण दिखाई नहीं देता है। आम आदमी के दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए न कोई विज़न है और न कोई विचार। ऐसा प्रतीत होता है कि देश और देश के लोगों को, जमाखोरों सट्टेबाजों, व्यापारियों तथा बाजारी ताकतों के रहमो–करम पर छोड़ दिया गया है। सरकार जड़िमा–ग्रस्त हुई प्रतीत होती है, जबकि आम आदमी अनियंत्रित मूल्यवृद्धि में राहत के लिए तरस रहा है।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की संप्रग– II सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर जो प्रेस कांफ्रेस 24 मई, 2010 को हुई थी, उसमें उनसे मुद्रास्फीति तथा मूल्यवृद्धि के कारण आम लोगों को हुई कठिनाइयों पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया था– "मूल्यवृद्धि एक बड़ा मुद्दा है जो सुलझ नहीं पाया है। मूल्यवृद्धि भारी चिंता का कारण बनी हुई है। सरकार मूल्यवृद्धि पर अकुंश लगाने को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है ताकि आम आदमी को कोई कठिनाई न हो। हम स्थिति पर सावधानीपूर्वक नजर रखेंगे और मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए, जो सुधारात्मक कदम जरूरी होंगे उनको उठाएंगे।" 1, जून 2010 को श्रीमती सोनिया गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा संप्रग– II के रिपोर्ट कार्ड में स्पष्ट उल्लिखित था – "मूल्य बढ़ गए हैं। खाद्य पदार्थों की मूल्यवृद्धि चिंता का बड़ा कारण है। सप्रंग–कांग्रेस सरकार इसका समाधान नहीं कर सकी है।" महामहिम! फरवरी 2010 में संसद के संयुक्त सत्र में आपके संबोधन में आपने भी आम आदमी और मध्यम वर्गों की चिंता को वाणी प्रदान की थी और सरकार को सलाह दी थी कि वह दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप तथा अन्य उपाय उठाकर प्रभावशाली हस्तक्षेप करे।

मगर इन चेतावनियों, आश्वासनों और वचनबद्धताओं के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि संप्रग सरकार आम आदमी की कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन हो गई है। दैनिक प्रयोग की प्रत्येक वस्तु के मूल्य कई गुना बढ़ गए हैं, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य विगत एक वर्ष में तीन बार बढ़ाए गए हैं। यह सुविदित है कि पेट्रोलियम के मूल्य में वृद्धि का देश की समग्र मूल्य स्थिरता पर भारी क्रमप्रपाती प्रभाव पड़ता है। इन सुस्थापित लिंकेजों के बावजूद मूल्यों में वृद्धि कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार के पार्ट पर घोर उपेक्षा और संवेदनहीनता की सूचक हैं।

यह ध्यान में आने से अतिशय वेदना होती है कि जबकि संप्रग/कांग्रेस सरकार के विभिन्न नेता और मंत्रीगण तरह–तरह की घोषणाएं कर रहे हैं तथा वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये घिसी–पिटी बातें शाब्दिक सहानुभूति की कवायद मात्र हैं।

वहां चोट करो जहां सबसे ज्यादा क्षति हो

ऐसा लगता है कि "गरीब हटाओ" संप्रग सरकार का आदर्श–वाक्य बन गया है। जबसे संप्रग सरकार सत्ता में आई है तब से गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। संप्रग – I तथा संप्रग – II के कार्यकाल के दौरान गरीबी बेतहाशा बढ़ी है। कांग्रेस के शासन में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। योजना आयोग के राष्ट्रीय नमूना सर्वे के अनुसार 2005 में

ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 28.3 प्रतिशत थी। मूल्यों में इस वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। यह चिंता की बात है कि सरकार इतना भी नहीं जानती है कि देश में गरीब लोगों की सही संख्या क्या है। योजना आयोग के अनुसार वे 28 प्रतिशत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एन.सी. सक्सेना समिति के अनुसार कैलोरी इनटेक के आधार पर देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 50 प्रतिशत है। असंगठित क्षेत्र हेतु गठित अर्जुन सेन गुप्ता समिति के अनुसार देश के 77 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 20 रूपए पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तेंदुलकर समिति रिपोर्ट के अनुसार 37.2 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। योजना आयोग ने अपनी 2005 की रिपोर्ट में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 31 करोड़ बताई थी। तेंदुलकर समिति ने दिसम्बर 2009 में यह संख्या 42 करोड़ बताई थी। ऐसे लोगों की दैनिक आय 20 रूपए से कम है। इस सारी गड़बड़ी के लिए कांग्रेस पार्टी और संप्रग सरकार की जन–विरोधी नीतियां जिम्मेवार है। अनियंत्रित मूल्यवृद्धि ने इन परिवारों के बच्चों के मुँह से निवाला छीन लिया है।

सब जगह गेहूं सड़ रहा है पर खाने के लिए एक भी दाना सुलभ नहीं है एक ओर यह त्रासदी है कि 58,000 करोड़ रूपए का खाद्यान्न गल–सड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वंचित लोगों को दिन में एक जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा के नेताओं ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में एफसीआई के गेहूं के खुले गोदामों का दौरा किया था और सड़े–गले गेहूं के नमूने इकट्ठे किए थे। संप्रग शासन की स्तब्ध करने वाली लापरवाही और खाद्य आपूर्ति मुद्दे के घोर कुप्रबंधन की बात संसद में उठाई गई थी। सड़े–गले गेहूं के नमूनों को सरकार को तथा माननीय अध्यक्ष को सौंपा गया था। यह जानकर धक्का लगा कि कांग्रेस सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई/सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण हजारों करोड़ रूपए का खाद्यान्न नष्ट हो जाने दिया गया, जबकि इन खाद्यान्नों के मूल्य आसमान छू रहे हैं और गरीब उन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। भाजपा महसूस करती है कि खाद्यान्न की महंगाई का कारण सरकार की लापरवाही, कुप्रबंधन और हेरा–फेरी है।

ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि एफसीआई/सरकार का लाखों टन गेहूं खुले वेयरहाउसों में सड़ रहा है। अप्रैल 2010 की स्थिति के अनुसार एफसीआई के पास केन्द्रीय पूल में 183 लाख टन गेहूं था। इसमें से 80 लाख टन (चार राज्यों में 72 लाख) गेहूं खुले वेयरहाउसों में पड़ा था, जो गल–सड़ गया है।

कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री शरद पवार ने कहा था कि यह हानि कुप्रबंधन के कारण हुई है। जबकि सरकारी गोदामों में प्रतिवर्ष लाखों टन खाद्यान्न सड़ जाते है, वहीं गरीब आदमी भूख और कुपोषण से मर रहे हैं। भारत सरकार की सक्सेना समिति ने कहा था कि गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों में से 51 प्रतिशत के पास कोई राशन कार्ड नहीं है। कांग्रेस–संप्रग शासन में किसानों को न्यूनतम प्राप्ति हो रही है, जबकि आम लोगों को अधिकतम भुगतान करना पड़ रहा है और आम लोग, गरीब तथा वंचित लोग खाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।

भारी पैदावार और विशाल बफर स्टॉक के बावजूद खाद्यान्नों के मूल्यों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भाजपा इसे हैरत की बात मानती है और राष्ट्र इस बफर स्टॉक को बाजार में जारी न करने अथवा इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित न किए जाने में असमर्थ है, जबकि इससे मूल्यों पर दबाव हल्का पड़ेगा। यह संप्रग सरकार द्वारा खाद्य अर्थव्यवस्था के घोर कुप्रबंधन और लापरवाही की घोर पराकाष्ठा है। एक ओर सरकार आम लोगों की हालत सुधारने और उनका कल्याण करने के लिए आंसू बहाती है वहीं यह मुनाफाखोरों के साथ मिलीभगत करके वस्तुओं का कृत्रिम अभाव कराती है ताकि उनके मूल्य बढ़ जाएं।

खाद्यान्न स्टॉक (संख्या लाखों में)

सरकार के अपने रिकार्ड से लिए गए उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते है कि 200 लाख टन की बफर स्टॉक अपेक्षा के विरूद्ध सरकार ने वस्तुतः 453 लाख टन का बफर स्टॉक रखा है। अतः कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार की घोर विफलता कुप्रबंधन और स्थिति को गलत ढंग से संभालने के अलावा अन्यथा मूल्यों में इस असाधारण मूल्य–वृद्धि की सफाई देना कठिन है।

	WHEAT	RICE	TOTAL
BUFFER NORMS	82	118	200
ACTUAL STOCKS	183.88	269.50	453.38

WHEAT IN CENTRAL POOL [FCI & STATE.AGENCIES] STORED IN Open Godowns as ON 1.04.2010 [FIG.IN MT]			
REGION	QTY.IN CAP/ OPEN GODOWNS		
	FCI	STATE AGENCIES	TOTAL
	48,226	41,57,486	42,05,712
HARYANA	59,559	24,85,351	25,44,910
RAJASTHAN	3,87,160	0	3.87,160
UTTAR PRADESH	98,453	0	98,453
TOTAL	5,93,398	66,42,837	72,36,235

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

भाजपा महसूस करती है कि संप्रग सरकार की गलत आर्थिक नीतियां आम आदमी के जीवन को दूभर बना रहीं हैं। गत एक वर्ष में कांग्रेस सरकार ने पेट्रोलियम के तीन बार मूल्य बढ़ाए हैं। सरकार ने कैरोसिन, सीएनजी आदि के मूल्य 33–46 प्रतिशत बढ़ाएं हैं।

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य

यह कांग्रेस ही थी, जिसने पेट्रोलियम के मूल्यों की स्थिरता को सुनिश्चित करने की वचनबद्धता दर्शायी थी। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 11 से लेकर 46 प्रतिशत की सहसा तेज वृद्धि, जिसका आम आदमी के रोजमर्रा जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ने मुद्रास्फीति/मूल्यवृद्धि को और अधिक बढ़ा दिया है। यह एक गलत सोचा गया कदम है। ऐसा लगता है कि मूल्यवृद्धि की घोषणा करते समय पेट्रोलियम के मूल्यों में इतनी भारी वृद्धि के परिणाम को नहीं आंका गया। इससे मूल्यों पर अंकुश लगाने के प्रयास और कठिन हो गए। इस तरह के अप्रत्यक्ष कर आम आदमी पर सीधा असर डालते हैं।

Products	Price in April, 2009 (in Rs.)	Price in July, 2010 (in Rs.)	% increase in last one year
Petrol	44.55	55.88	25
Diesel	34.45	41.98	20
Kerosene	9.05	12.27	33
CNG	21.70	31.47	46
Cooking Gas (LPG)	312.05	348.45	11

Note : Petroleum products price differs from State to State due to SST/VAT.

मूल्यवृद्धि - अन्य देशों तथा अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना

जहां विश्व में 1–3 प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुई है वहीं भारत में द्विअंकीय मूल्यवृद्धि हुई है। डॉ मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए इस तर्क को समझना/स्वीकार करना कठिन है – "यदि आप विकास चाहते हैं तो आपको मुद्रास्फीति झेलनी पड़ेगी।" चीन, ब्राजील और रूस विश्व में सर्वाधिक विकासशील अर्थव्यवस्थाएं है। जहां चीन में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 9.5 प्रतिशत है, वहीं भारत में 7.2 प्रतिशत है, किन्तु चीन में मूल्यवृद्धि 3 प्रतिशत और खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि 1 प्रतिशत है, वहीं भारत में मूल्य वृद्धि लगभग 11 प्रतिशत है।

Country	Inflation %
China	2.7
America	2.6
South Korea	2.7
Europe	0.9
Hong Kong	1.0
Taiwan	2.4
Malaysia	1.3
Singapore	0.2
India	11+
Data : May/June 2010	

विश्व के विभिन्न देशों में आवश्यक वस्तुओं, तथा खाद्यान्नों के मूल्य कम हुए हैं। कई मदों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारत की अपेक्षा आधे हैं। चीनी एक अनोखा उदाहरण है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 17 रूपए है। जबकि भारत में आम उपभोक्ता 38/– रूपए प्रतिकिलो का भुगतान करने के लिए विवश है।

Total Turnover		Speculation		Actual Delivery	
Amount Rs. Crores	%	Amount Rs. Crores	%	Amount Rs. Crores	%
10,88,224	100	10,84,633	99.67	3,591	0.33

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भारत में विश्व की तुलना में दोगुने है

वस्तु विनिमय - सट्टेबाजी के अड्डे

गलत आर्थिक नीतियों के साथ अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से आम आदमी पर कर थोपने सट्टेबाजी और वस्तु विनिमय पर आवश्यक वस्तुओं की हेरा–फेरी ने खाद्य मूल्य वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में लगभग 22–23 वस्तु विनिमय है। इनमें से National Commodity – Derivative Exchange (NCDEX) और Multi Commodity Exchange (MCX) बड़े विनिमय हैं। आवश्यक अर्थात् कृषि वस्तुओं का व्यापार मुख्यतः Commodity Exchange (NCDEX) पर किया जाता है। 2009 में NCDEX पर 10.84, 224 करोड़ रूपए के टर्नओवर में से डिलीवरी 0.33 प्रतिशत अर्थात् 3,591 करोड़ रूपए हुई। कृत्रिम टर्नओवर खाद्यान्नों/ वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाता है।

Item	Rate per kg	
	International Price	Price in India
Wheat	8.00	14.50
Soyabean	16.24	22.50
Soya Oil	40.06	46.00
Sugar	17.68	38.00

भारत सरकार मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तुओं अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कह रही है। इसके विपरीत वह Commodity Exchange पर आवश्यक वस्तुओं में अगाऊ व्यापार करने/की अनुमति देकर Speculative,

Manipulative प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। उपर्युक्त आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि कृषि/आवश्यक वस्तुओं में 99.67 प्रतिशत लेन–देन सट्टा–आधारित हैं। इससे कीमतें ऊंची हो जाती हैं। 2004 (उत्तरार्ध) से आवश्यक वस्तुओं को Future Trading में शामिल कर लिया गया है। स्थिति की गंभीरता, आम लोगों, किसानों मध्यम वर्गों और कामगारों की कम न होने वाली कठिनाइयों, कांग्रेस पार्टी और संप्रग सरकार द्वारा लोगों की आवाजों के प्रति आंख और कान मूंदकर दिखाई जाने वाली घोर उपेक्षा संवेदनहीनता और उदासीनता को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी मुल्यवृद्धि के मुद्दे पर आंदोलन की अगुवाई कर रही है ताकि सरकार निकम्मेपन और भटकाव का रवैया त्यागे और स्थिति को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए।

16 जनवरी, 2010 से भारतीय जनता पार्टी कम न होने वाली मूल्यवृद्धि के विरूद्ध सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही है और विभिन्न प्लेटफार्म के माध्यम से, विभिन्न स्तरों पर मूल्यवृद्धि/महंगाई के मुद्दे को उठा रही है।

I भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने देश के 15 विभिन्न राज्यों/शहरों में मूल्यवृद्धि पर Power Point Presentation किया है।

II भाजपा ने 20 फरवरी 2010 को प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया।

III भाजपा–नीत प्रतिपक्षी पार्टियों ने संसद में 25 फरवरी, 2010 को मूल्यवृद्धि पर बहस शुरू की।

IV विभिन्न राज्य विधानमंडलों में इस मुद्दे पर बहस की गई।

V सरकार का ध्यान गेहूं सड़ने के मुद्दे की ओर और इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद लोगों में वितरित करने की ओर ध्यान आकर्षिक करने के लिए भाजपा नेताओं ने सरकार के/एफसीआई के खुले गोदामों का दौरा किया।

VI भाजपा नेताओं ने देश में आलू की खेती करने वाले विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और सरकार का ध्यान इस उदासीनता/विषमता की ओर खींचा कि एक आलू के किसान को 2/– से लेकर 4/– रूपए प्रतिकिलो की प्राप्ति होती है जबकि उपभोक्ता 10/– से लेकर 18/– रूपए प्रति किलो का भुगतान करता है।

VII विगत 6 मास के दौरान देशभर में महंगाई मार्च/रैली – प्रदर्शन आयोजित किए।

VIII आम आदमी की पीड़ाओं को व्यक्त करने और इस आराम से सोने वाली तथा निकम्मी संप्रग सरकार को जगाने के लिए भाजपा ने 21 अप्रैल, 2010 को मूल्यवृद्धि के विरूद्ध दिल्ली में एक विशालकाय रैली आयोजित की।

IX अप्रैल 2010 के पिछले सप्ताह में संसद में महंगाई/मूल्यवृद्धि के मुद्दे पर में एक बार पुनः चर्चा की गई।

X 5 जुलाई को भारत बंद आयोजित किया गया।

आज भारतीय जनता पार्टी मूल्यवृद्धि के विरूद्ध आम लोगों के करोड़ों हस्ताक्षर पेश कर रही है। हमारी मांग है कि सरकार देश में मूल्यवृद्धि रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए :

I Commodities Exchange Forward Trading List से खाद्य वस्तुओं को अलग करे।

II खाद्य सुरक्षा करे तथा बफर स्टॉक बनाए।

III किसानों और आम आदमी को लूटने–खसोटने की आर्थिक नीति बंद की जाए।

IV गेहूं, चावल, चीनी, दाल और हरी सब्जियों के मूल्य कम करने के कदम उठाए जाएं।

V जमाखोरों, कालाबाजारियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, कार्पोरेट की हेरा–फेरी और मुनाफाखोरों के विरूद्ध कार्रवाई पर निगाह रखी जाए।

VI खाना रसोई के लिए हो (केवल विचार के लिए न हो।

VII कृषि अर्थव्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

VIII कृषि विकास और कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए समुचित धन का आबंटन किया जाए।

IX जल तथा नदी परियोजनाओं पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए।

X खाद्यान्नों और उद्यान भंडारण का समुचित प्रबंध किया जाए।

XI अगले 25 वर्षों के लिए भरी–पूरी भंडारण योजना बनाई जाए।

संप्रग सरकार की गलत आर्थिक नीतियां :

कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार की आयात–निर्यात, कृषि, उपभोक्ता मामले, त्रुटिपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य और सिविल सप्लाई गड़बड़ी, खराब भंडारण सुविधाएं, वित्तीय नीतियां तथा केन्द्रीय सरकार का कुप्रबंधन तथा जोड़–तोड़, भ्रष्टाचार यह सभी कारक वर्तमान महंगाई के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। हमारा अनुरोध है कि आप मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगवाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि आम आदमी को कुछ राहत मिल जाए।

सादर,

आपके

fufru xMdjh
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

ykyÑ".k vkMok.kh
चेयरमैन – भाजपा संसदीय दल

l"kek Lojkt
नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा)

v:.k tsVyh
नेता प्रतिपक्ष (राज्यसभा)

जनांदोलन

भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के दर्द को महसूस करते हुए महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किए।

21 अप्रैल, 2010

केन्द्र की गलत आर्थिक नीतियों और कुशासन के चलते महंगाई बढ़ी

गत 21 अप्रैल, 2010 को यूपीए सरकार की गलत नीतियों से बेलगाम हुई महंगाई के विरोध में भाजपा के आह्वान पर देश के कोने–कोने से आए लाखों लोगों ने संसद पर दस्तक दिया और कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार को चेतावनी दी कि 'महंगाई रोक दो–वरना गद्दी छोड़ दो'।

महंगाई से आम आदमी किस कदर परेशान हैं इसकी बानगी रामलीला मैदान में स्वतः ही दृश्यमान हो रही थी। वर्षों बाद लोगों का सैलाब इस कदर उमड़ा कि यह मैदान छोटा पड़ गया। जितने लोग रामलीला मैदान में थे उतने ही लोग दिल्ली की सड़कों पर। भारत की राजधानी महंगाई विरोधी नारों से गूंज उठी। महंगाई के विरोध में रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इसके पश्चात् लाखों प्रदर्शनकारियों ने एक हाथ में भाजपा का झंडा तो दूसरे हाथ में तख्ती लिए संसद की ओर मार्च किया। तख्तियों पर– 'सोनिया–मनमोहन की जोड़ी, आम आदमी की कमर तोड़ी', 'सोनिया का देखो खेल, महंगी चीनी महंगा तेल', 'कांग्रेस का हाथ, जमाखोरों के साथ', 'जबसे कांग्रेस आई है, कमरतोड़ महंगाई है', 'घेरो संसद बांधो दाम, महंगाई पर कसो लगाम', आदि महंगाई विरोधी नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रंजीत फ्लाई ओवर के सामने रोक दिया। लेकिन हजारों लोग जंतर–मंतर तक पहुंचने में सफल हो गए, जहां एक सभा के बाद महारैली समाप्त हो गई।

जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने संप्रग सरकार को

गांव, गरीब और मजदूर विरोधी सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि 'गरीबी हटाओ' के नाम पर कांग्रेस सरकार गरीबों को हटाने पर तुली हुई है। इस सरकार के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। दाल, चावल और चीनी का घोटाला हुआ। गोदामों में अनाज सड़ रहा है। आम आदमी दाने–दाने को मोहताज है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इस सरकार ने गरीब आदमी के पेट पर लात मारी है, हमें इसके खिलाफ लड़ना है।

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित यह पहली रैली असाधारण है। इसने पूर्व की सभी रैलियों को मात दे दी है। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर यह सरकार पूरी तरह विफल हुई है। कार्यक्रम को पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह,लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण श्री शिवराज सिंह चौहान (मध्यप्रदेश), डा. रमन सिंह (छत्तीसगढ़), प्रो. प्रेमकुमार धूमल (हिमाचल प्रदेश), श्री सुशील कुमार मोदी, (उपमुख्यमंत्री, बिहार) दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कोहली ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार, श्री कलराज मिश्र, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्रीमती किरण घई, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्रीमती नज़मा हेपतुल्ला, श्री विनय कटियार, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल, सह–संगठन मंत्री श्री व्ही. सतीष, श्री सौदान सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री थावरचंद गहलोत, श्रीमती वसुन्धराराजे, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री अर्जुन मुण्डा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर राष्ट्रीय सचिव श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री वरुण गांधी, सुश्री सरोज पाण्डेय, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री किरीट सौमेय्या, सुश्री वाणी त्रिपाठी, श्री भूपेन्द्र सिंह, इसके अलावा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता, लोकसभा में उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे, राज्यसभा में उपनेता श्री एस.एस. अहलूवालिया, राज्यसभा में मुख्य सचेतक श्रीमती माया सिंह, झारखण्ड के उपमुख्यमंत्री श्री रघुवरदास, कमल संदेश के सम्पादक श्री प्रभात झा, भाजपा केन्द्रीय कार्यालय प्रभारी श्री शाम जाजू, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर, श्री शहनवाज हुसैन, श्री तरुण विजय, श्री रामनाथ कोविद, श्रीमती निर्मला सीता रमण आदि तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' भी उपस्थित थे। सभा का संचालन राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल ने किया।

30 जून, 1 व 2 जुलाई, 2010

भाजपा का देशव्यापी महंगाई विरोधी जन आंदोलन कार्यक्रम सम्पन्न

यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में वृद्धि एवं बेलगाम बढ़ती महंगाई के विरोध में 30 जून, 1 व 2 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा "महंगाई विरोधी जन आंदोलन कार्यक्रम" देशभर के विभिन्न स्थानों में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्मलित हुए। रतलाम (मध्यप्रदेश) में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी एवं पार्टी महासचिव, श्री अनंत कुमार ने भाजपा मध्यप्रदेश की कार्यसमिति को सम्बोधित किया उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं श्री थावरचंद गहलोत भी उपस्थित थे। इसके पश्चात् श्री गडकरी ने रतलाम में आयोजित प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मेलन को भी सम्बोधित किया। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई, यूपीए सरकार की विफलता, भोपाल गैस त्रासदी एवं सीबीआई के दुरूपयोग जैसे मुद्दों पर केन्द्र सरकार को आड़े हाथ लिया तथा केन्द्र सरकार से भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी एंडरसन के तुरंत प्रत्यर्पण की मांग की। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के लिए एवं प्रदेश में चल रहे जरूरी विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक राशि देने की मांग की। भुवनेश्वर (उड़ीसा) में आयोजित रैली को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री राजनाथ सिंह ने सम्बोधित किया। इस रैली में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, श्री भूपेन्द्र यादव एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित हुए। रांची (झारखंड) में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में राजभवन के सामने विशाल धरना–प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरने में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अर्जुन मुंडा, श्री पी.एन. सिंह आदि वरिष्ठ नेता भी सम्मिलित हुए। चंडीगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल के नेतृत्व में घोड़ा–गाड़ी रैली आयोजित हुई। इस रैली में चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय टंडन एवं वरिष्ठ नेता सहित हजारों कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती स्मृति ईरानी के नेतृत्व में धरना–प्रदर्शन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा एवं प्रदेश पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी।

देहरादून (उत्तराखंड) में एक दिवस पूर्व ही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कलराज मिश्र ने एक बड़ी सभा को सम्बोधित किया। इस सभा को उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री बिशन सिंह चुपाल एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने भी सम्बोधित किया। इसी क्रम में अलवर (राजस्थान) में आयोजित विशाल रैली को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्री विनय कटियार एवं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री अशोक प्रधान ने सम्बोधित किया।

इस रैली में बड़ी संख्या में अलवर एवं आस–पास के क्षेत्रों की आम जनता सम्मिलित हुई। वहीं भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश ने जालंधर (पंजाब) में "थाली खड़काऊ" नामक महंगाई विरोधी कार्यक्रम आयोजित किया जिस कार्यक्रम को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री जे.पी. नड्डा ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार सोई हुई है और आम जनता महंगाई से त्रस्त है। एक दिवस पूर्व ही पटना (बिहार) में आयोजित एक विशाल धरने को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी ठाकुर एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारियों ने भी सम्बोधित किया।

पणजी (गोवा) में आयोजित एक जनसभा को लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे ने सम्बोधित किया। सांयकाल मुंबई (महाराष्ट्र) में एक जनसभा को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सम्बोधित किया। सांयकाल को नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित जनसभा को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद ने सम्बोधित किया।

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर एवं हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष श्री खिरीराम ने देहरा (कांगड़ा) में आयोजित एक जनसभा को सम्बोधित किया। वहीं बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में महंगाई के विरोध में एक विशाल धरना–प्रदर्शन का आयोजन किया गया जिसे भाजपा की राष्ट्रीय सचिव सुश्री सरोज पांडेय ने सम्बोधित किया।

इसी क्रम में 2 जुलाई को भी विभिन्न राज्यों में रैली व जनसभा आयोजित हुई। प्रमुख रूप से लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज रायपुर (छत्तीसगढ़) में आयोजित जनसभा को सम्बोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय सचिव सुश्री वाणी त्रिपाठी भी उपस्थित रहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, श्री एम. वैंकेया नायडू ने चेन्नई (तमिलनाडु) में आयोजित जनसभा को सम्बोधित किया। वहीं अहमदाबाद (गुजरात) में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार एवं राष्ट्रीय सचिव श्री किरीट सौमय्या ने सभा को सम्बोधित किया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नितिन गडकरी ने 4 जुलाई को लखनऊ में आयोजित महंगाई विरोधी विशाल रैली को सम्बोधित किया।

5 जुलाई, 2010 को 'भारत बंद''

सड़क से संसद तक संघर्ष

5 जुलाई के भारत के बंद को जनता ने अभूतपूर्व सफल बनाया। यह बंद इतना स्वयंस्फूर्त था कि 70 के दशक के स्व. जयप्रकाश के नेतृत्व वाली जन–आंदोलन वाली याद आई। बंद की इस अप्रत्याशित सफलता के लिए जनता को हम बधाई देते हैं। अनेक वर्षों के बाद देश ने ऐसा बंद देखा और साकार किया। जिन्होंने बंद के आंदोलन में सहभाग दिया, ऐसी सभी पार्टियों को भी हम बधाई देते हैं।

पिछले दिनों में भी जनता ने महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जताया, लेकिन सरकार ने असंवेदनशीलता का परिचय दिया। सरकार के रवैये की हम भर्त्सना करते हैं। हम मांग करते हैं कि आज के जन–आंदोलन की भावना को समझकर पेट्रोल, डीज़ल, कैरोसीन एवं एलपीजी के बढ़ाए गए दाम तुरंत वापस लिया जाए।

अब भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो वह लोकतंत्र का अपमान होगा, जन–भावना की उपेक्षा होगी, लोक इच्छा का विरोध होगा। यह अद्‌भुत आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से हुआ। नक्सलवादी गोली की भाषा बोलते है, अलगाववादी पत्थर और आतंक की भाषा बोलते है, हमने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई शुरू की है। नतीजा आने तक यह जारी रहेगी। अब या तो महंगाई कम होगी या जन–विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा।

अब सरकार पर नोटिस पर रहेगी। एनडीए बैठक करेगी और आने वाले दिनों के लिए अपनी रणनीति बनाएगी। संसद के वर्षाकालीन सत्र में यह विषय जोरदार तरीके से उठाएंगे।

गरीब के सम्मानपूर्वक जीने के हक को हम मुद्‌दा बनाएंगे और गैर कांग्रेस सभी दलों को इस लड़ाई को एकजुट तरीके से लड़ने का हम आह्‌वान करते हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में भारत बंद का नेतृत्व स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नितिन गडकरी ने किया। दिल्ली के चांदनी चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि आज का भारत बंद आम जनता का बंद है। कुछ लोगों को दिक्कत अवश्य रही होगी, लेकिन कुंभकर्ण की नींद

सो रही सरकार को जगाने के लिए एक दिन दिक्कत कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। महंगाई के खिलाफ यह लड़ाई भाजपा की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की लड़ाई है और देश की जनता आज इस लड़ाई को सड़क पर लड़ रही है। पूरे देश में शांतिपूर्ण बंद इसका उदाहरण है। देश की जनता यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी से पूछना चाहती है कि महंगाई के नाम पर आप चुप क्यों है ? आज देश की जनता सड़क पर आकर सोनिया जी से पूछ रही है कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि महंगाई आखिरकार कब कम होगी ? पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल, श्री जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय सचिव सुश्री वाणी त्रिपाठी, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक श्री श्रीकांत शर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा हजारों कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में आयोजित एक जनसभा के पश्चात् गिरफ्तारी दी। दिल्ली के सभी प्रमुख बाजार बंद रहे। कई प्रमुख चौक, चौराहों पर चक्का जाम रहा। यातायात व्यवस्था ठप्प पड़ गई, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्यप्रताप शाही, वरिष्ठ नेता श्री लालजी टंडन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री रमापति त्रिपाठी ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। राजभवन का घेराव किया गया। पुलिस बल ने भारी लाठी चार्ज किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए। पुलिस ने सभी वरिष्ठ नेताओं और हजारों नेताओं को गिरफ्तार किया। बनारस (उत्तर प्रदेश) में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया व गिरफ्तारी दी।

भोपाल (मध्यप्रदेश) में लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा के नेतृत्व में भारत बंद का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक स्तर तक में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बंद पूर्णतः सफल रहा। श्रीमती सुषमा स्वराज ने पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए केन्द्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया।

हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बंडारू दत्तात्रेय के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन आयोजित हुआ प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन रेड्डी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विद्या सागर राव, राष्ट्रीय सचिव डॉ. लक्ष्मण सहित 1000 कार्यकर्ता राज्य भवन की ओर कूच करते हुए गिरफ्तार हुए। प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी।

पटना (बिहार) में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद तथा बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री सी.पी. ठाकुर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। वरिष्ठ नेताओं सहित सैंकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। पटना शहर एवं बिहार के प्रमुख शहर पूरी तरह बंद रहे। कई ट्रेनें रूकी रहीं। यातायात व्यवस्था ठप्प पड़ गई। आम जनता ने भी इस बंद में बड़ी संख्या में भागीदारी की।

महाराष्ट्र में लोकसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री किरीट सौमय्या, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधीर मुगंतिवार मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल शेट्टी तथा भाजपा के सभी सांसदों आदि के नेतृत्व में विभिन्न स्थलों पर विरोध प्रदर्शन अयोजित किया गया एवं गिरफ्तारियां हुई। पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए।

तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष श्री पोन राधाकृष्णन एवं वरिष्ठ नेता श्री एल. गणेशन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया व गिरफ्तारी दी। तमिलनाडु के सभी जिला मुख्यालयों पर भी विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए तथा जगह–जगह कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी।

बंग्लौर (कर्नाटक) में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री के.एस.

ईश्वरप्पा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा गिरफ्तारियां दी गई। कर्नाटक में बंद पूर्णतः सफल रहा। सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन आयोजित हुए, गिरफ्तारियां हुई, दो जिला मुख्यालयों में लाठी चार्ज हुआ।

हिमाचल प्रदेश में भाजयुमो के अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर ने परमारू व सोलन में महंगाई विरोधी कार्यक्रमों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार महंगाई के मामले में चुप क्यों है देश की जनता जानना चाहती है ? हिमाचल प्रदेश में बंद पूर्णतः सफल रहा। छोटे–बड़े सभी शहरों और कस्बों में बंद का प्रभाव दिखा।

रायपुर (छत्तीसगढ़) में भारत बंद का व्यापक प्रभाव देखने को मिला। छोटे–बड़े शहर, गांव व कस्बों में भी कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की जन–विरोधी नीतियों के विरोध में जनता ने स्वयं स्फूर्त अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री थावरचंद गहलोत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती करूणा शुक्ला ने रायपुर में और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुश्री सरोज पांडेय ने दुर्ग में प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

जयपुर (राजस्थान) भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती वसुंधरा राजे व प्रदेश अध्यक्ष श्री अरूण चतुर्वेदी के नेतृत्व में भारत बंद का आयोजन किया गया। प्रातः से ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन आरंभ किया। छोटे–बड़े सभी शहरों में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यातायात व्यवस्था पूर्णतः लगभग ठप्प रही।

केरल में प्रदेश अध्यक्ष श्री वी. मुरलीधरन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। सभी जिला मुख्यालयों में जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए। केरल में भी भारत बंद को आम जनता का समर्थन प्राप्त हुआ।

रोहतक (हरियाणा) में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिमन्यु एवं भाजपा मुख्यालय प्रभारी श्री श्याम जाजू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, गिरफ्तारियां दी, हरियाणा के विभिन्न शहरों में बंद शांतिपूर्ण रहा। आम जनता ने स्वयं स्फूर्त अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और भारत बंद का समर्थन किया।

गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालय ब्लॉक स्तर सभी छोटे–बड़े शहर में बंद को भारी जन समर्थन मिला। बंद पूर्णतः सफल रहा।

पांडेचरी में प्रदेश अध्यक्ष एस.पी.के. दामोदर के नेतृत्व में भारत बंद का आयोजन हुआ। सभी स्कूल, कॉलेज, शासकीय एवं प्राइवेट प्रतिष्ठान बंद रहे। यातायात ठप्प रहा।

इसी प्रकार उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर राज्य एवं गोवा आदि सभी प्रदेशों में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यातायात व्यवस्थाएं ठप्प रहीं। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। जगह–जगह विरोध प्रदर्शन आयोजित हुए। आम जनता ने बंद में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। गिरफ्तारियां हुईं। पूरे देशभर में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के जन–विरोधी नीति के विरूद्ध भारी जन–आक्रोश देखने को मिला। भारत बंद पूर्णतः सफल रहा।

22 दिसम्बर, 2010

राजग की प्रधानमंत्री से मांग जेपीसी गठित करें या पद छोड़ें

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में संघर्ष के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सड़कों पर उतर आई। गत 22 दिसम्बर, 2010 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा नई दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरूद्ध आयोजित महासंग्राम रैली को गठबंधन के घटक दलों–भारतीय जनता पार्टी, जनता दल(यूनाइटेड), शिवसेना और अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। रैली में हजारों लोगों की संख्या में महिलाओं और युवाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। रैली को संबोधित करते हुए राजग के कार्यकारी अध्यक्ष व भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने अधिकारों का प्रयोग कर घोटाले की जांच के लिए जेपीसी का गठन करना चाहिए। उनमें यह साहस होना चाहिए कि वे जेपीसी के सामने जवाब देने के लिए हाजिर हो सकें। उन्होंने कहा, 'हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री इस बात के लिए इंतजार करते हैं कि 10 जनपथ क्या कहता है।'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि केन्द्र की सरकार देश को लूटने वाली सरकार है। इस सरकार के दूल्हा हैं ए. राजा और बाराती हैं कांग्रेस में बैठे दलाल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की मांग को नहीं मानकर देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने 2जी घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की एक बार फिर मांग की। श्री गडकरी ने कहा कि आज जो भी घोटाले हो रहे हैं वह कांग्रेस शासित राज्यों में हो रहे हैं। महाराष्ट्र में आदर्श आवास सोसाइटी, जो शहीदों के नाम पर बना था, उसमें 70 प्रतिशत आवास कांग्रेस नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को दिया। श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर में भ्रष्टाचार खत्म करे फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात करे।

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि विपक्ष ने जेपीसी की मांग 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को सुगम बनाने के लिए की थी, लेकिन कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार ने इरादतन इसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि यह उसके छिपे ढांचे को उजागर कर सकती थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि यदि वह 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच का सामना करने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राजग के राष्ट्रीय संयोजक श्री शरद यादव, शिव सेना संसदीय दल के नेता श्री अनंत गीते और अकाली दल के वरिष्ठ नेता श्री रतन सिंह अजनाला ने भी रैली को संबोधित किया। इस महासंग्राम रैली का संचालन दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल ने किया। इस महासंग्राम रैली के दौरान भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू एवं राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, लोकसभा में पार्टी के उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता श्री एस.एस. अहलूवालिया, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी आदि वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ■

संगठनात्मक कार्यक्रम

इंदौर : राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद बैठक

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 18 एवं 19 फरवरी, 2010 को कुशाभाऊ ठाकरे ग्राम, इंदौर में सम्पन्न हुयी। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपना पहला अध्यक्षीय उद्‌बोधन दिया। श्री गडकरी ने अपने प्रेरणास्पद एवं ओजस्वी भाषण में कहा कि कांग्रेस की नीतियां देश को खतरे में धकेल रही है। कांग्रेस के पास किसी समस्या का समाधान नहीं है। भाजपा के पास देश की तकदीर बदलने की ताकत है। बैठक में दो प्रस्ताव आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पारित किये गए एवं श्री लालकृष्ण आडवाणी ने मार्गदर्शन उद्‌बोधन दिया।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक और बिहार स्वाभिमान रैली

भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक गत 12–13 जून को पटना के होटल मौर्य परिसर (चाणक्य नगर) में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 252 सदस्यों ने हिस्सा लिया।

कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने जहां बिहारवासियों से आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा राजग की सरकार बनाने की अपील की, वहीं आतंकवाद, नक्सलवाद, महंगाई और सी.बी.आई. के गलत इस्तेमाल जैसे राष्ट्रीय विषयों पर केन्द्र की यूपीए सरकार को विफल बताया। बैठक में राष्ट्रीय महत्व के तीन प्रस्ताव भी पारित हुए। पहला प्रस्ताव नक्सली हिंसा से संबंधित

था तो दूसरा यूपीए–2 के कार्यकाल के पहले वर्ष की विफलताओं से संबंधित था। तीसरा प्रस्ताव केन्द्र सरकार द्वारा भारत के संघीय ढांचे को आघात पहुंचाने के बारे में था।

केन्द्र सरकार की वर्तमान विदेश नीति की आलोचना करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि यूपीए गठबंधन की सरकार नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अमरीका व अन्य देशों के साथ केवल प्रतिक्रियात्मक विदेश नीति का अनुसरण कर रही है। सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर अमरीका की बंधक बनी हुई है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के अवसर पर 13 जून को पटना के गांधी मैदान में भाजपा ने बिहार स्वाभिमान रैली आयोजित की। इसमें बिहार के कोने–कोने से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार के दौरे पर आए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह भाजपा की संस्कृति है कि उनके जैसा साधारण कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस में यह पद सिर्फ गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। कांग्रेस घोर जातिवाद और साम्प्रदायिकता की राजनीति कर रही है। उसके कुशासन के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। कृषि मंत्री ने माना है कि 58 हजार करोड़ रुपए का अनाज सड़ गया। सीबीआई का दुरुपयोग कर कांग्रेस अपनी सत्ता चला रही है। एंडरसन मामले में प्रणव मुखर्जी के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यदि भोपाल के हालात एंडरसन के लिए ठीक नहीं थे तो उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बिहार में हवा में आसन्न चुनावों की खनक महसूस की जाने लगी है। ऐसे में श्री गडकरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा गठबंधन धर्म का बेहतर तरीके से पालन करेगी, मगर अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी।

रैली में पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सर्वत्र प्रशंसा का केन्द्र बने गुजरात के विकास से बात आरम्भ करते हुए कहा, 'गुजरात की प्रगति में एक हिस्सा सुशासन और ईमानदारी का है तो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा स्वाभिमान का है। इसलिए बिहार के तीव्र विकास हेतु बिहार का स्वाभिमान जगना आवश्यक है। कार्यक्रम को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने भी संबोधित किया। मंच संचालन राजग के प्रदेश संयोजक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री नंद किशोर यादव ने किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. सी.पी. ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का अभिनंदन किया।

इस्रायल में भाजपा अध्यक्ष का भव्य स्वागत

भारत–इस्राइल के बीच सम्पर्क व संवाद बढ़ाने की जरूरत

हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने इस्रायली सरकार के आमंत्रण पर इस्रायल की सद्भावना यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य था कृषि, सिंचाई, जल–प्रबंधन, नवीनकरणीय ऊर्जा, फसल उत्पादन, नेनोटेक्नालॉजी और बायोटेक्नालॉजी क्षेत्रों के आपसी हितों जैसे विषयों पर संयुक्त भारत–इस्रायल अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का अध्ययन करना।

श्री गडकरी जी की छह दिन की यात्रा में उनके शिष्टमण्डल में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल थे जिनमें राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय महामंत्री तथा पूर्व राजस्थान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनकड़, के साथ–साथ श्री सतपाल मलिक, श्री सुभाष देशमुख और मानवेन्द्र सिंह (सभी पूर्व–सांसद) और श्री विजय जौली, सह–संयोजक, भाजपा विदेश कार्य प्रकोष्ठ भी शामिल थे।

भाजपा अध्यक्ष की यात्रा का उद्देश्य यह भी था कि हम भारत और इस्रायल के बीच जन से जन सम्पर्क को बढ़ावा दें। इस्रायली विदेश मंत्रालय की ओर से 2009 के अन्तर्राष्ट्रीय सर्वे में यह कहा गया है कि विश्व में भारत ही सर्वाधिक इस्रायल–समर्थक देशों में आता है।

इस्रायल की संसद में शिष्टमण्डल का भव्य स्वागत

16 दिसम्बर को इस्रायली 'क्नेसेट' (संसद) के स्पीकर ने भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी और उनके शिष्टमण्डल का विशिष्ट आगन्तुक दीर्घा में तथा ट्रजरी और विपक्ष के सदस्यों ने ताली बजाकर एवं डेस्क थपथपा कर भव्य स्वागत किया।

बाद में इस्रायली उप प्रधानमंत्री श्री डान मेरीडोर ने बताया कि आज संसद के सत्ताधारी और विपक्षी सदस्यों ने अपनी सारी परम्पराएं और नियम तोड़कर आपका स्वागत मेजें थपथपाकर किया है, वह अपने आप मे अभूतपूर्व है।

अनुसंधान और विकास उद्यमों का दौरा

16 दिसम्बर को ही श्री गडकरी और शिष्टमण्डल ने कृषि–तकनीकी उद्योगों, सिंचाई और जल प्रबंधन क्षेत्रों के आपसी हितों से जुड़े अनुसंधान और विकास संयुक्त उद्यमों का दौरा करते हुए बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखण्ड जैसे क्षेत्रों में विस्तार करने पर अपनी सहमति जताई।

इस्रायली उप–प्रधानमंत्री ने श्री गडकरी को आश्वस्त किया कि इस्रायली सरकार को कार्ययोजना 2008–2010 के कार्यक्षेत्र को भारत के राज्यों मे भी विस्तार करने में प्रसन्नता होगी। इस कार्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को 'सिनाडको' के विशेषज्ञों की मदद से विस्तार किया जाता है।

श्री गडकरी का राजनैतिक स्तर पर जन सम्पर्क को बढ़ावा देने का आह्वान

17 दिसम्बर को तेल अवीव में इस बात पर जोर दिया कि भारत और इस्रायल को अपने देशों के बीच जन से जन सम्पर्क के विषय में राजनैतिक स्तर पर संवाद करने उनके बीच सम्पर्क बढ़ाने की जरूरत है ताकि आपसी हितों में मामले में एक दूसरे के साथ बंधन और मजबूत हो सकें। यह बात इस्रायल की सत्ताधारी एवं विपक्ष की पार्टियों के साथ हुई मुलाकातों के बीच उभर कर सामने आई।

श्री गडकरी और उनके शिष्टमण्डल ने इस्रायली 'क्नेसेट' (संसद) की विपक्ष की नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुश्री ट्जीपीलिवनी और पार्लियामेंट्री इण्डिया–इस्रायल ग्रुप के अध्यक्ष सुश्री रेशेल अदात्तो, दोनों ही मुख्य विपक्षी कदीमा पार्टी से जुड़ी है, सत्ताधारी लिकुड पार्टी और उप–प्रधानमंत्री श्री डान मेरीडोर के साथ मुलाकात की।

प्रधानमंत्री नेतान्याहू द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध भारत का समर्थन

18 दिसम्बर को जेरूसलम में इस्रायल के प्रधानमंत्री श्री बेंजमिन नेतान्याहू ने फिर पुष्ट किया कि इस्रायल हर प्रकार से आतंकवाद के साथ लड़ने में भारत के साथ सहयोग करने के प्रति वचनबद्ध है।

उन्होंने भाजपा अध्यक्ष श्री गडकरी को बताया कि इस्रायल भारत की सुरक्षा के प्रति चिंता में शामिल है और इस सम्बंध में नई दिल्ली के साथ सहयोग कर रहा है।

इस्रायली प्रधानमंत्री ने श्री गडकरी से फोन पर बात की और उन्हें इस्रायली सरकार के आमंत्रण पर इस्रायल यात्रा करने के लिए धन्यवाद दिया।

भारत सरकार की औद्योगिक नीति और प्रोमोशन विभाग उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से अप्रैल 2010 तक इस्रायल से भारत को एफडीआई का प्रवाह 51.87 मिलियन यूएस डालर बैठता है। बहुत सी इस्रायली कम्पनियों में अमेरिका और यूरोप के देशों के माध्यम से भी निवेश किया है।

चीनी उप विदेशमंत्री की भाजपा अध्यक्ष गडकरी से भेंट

गत 17 अगस्त को पीपुल्स चीन गणराज्य के सात सदस्यों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री श्री एईपिंग की अगुआई में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के साथ भाजपा मुख्यालय में आकर भेंट की। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। भाजपा अध्यक्ष के साथ ओवरसीज फ्रैण्ड्स आफ बीजेपी के सह संयोजक श्री विजय गोयल तथा भाजपा अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव श्री विनय सहस्रबुद्धे इस मुलाकात में साथ थे। यह मुलाकात आधे घण्टे तक चली। दोनों पक्षों के नेताओं ने भारत–चीन सम्बंधों को प्रोत्साहित करने और दृढ़ करने की इच्छा प्रगट की।

अर्जुन मुंडा तीसरी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री

झारखण्ड में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने 11 सितम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनकी अगुवाई में भाजपा, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और ऑल झारखण्ड स्टूडेंटस यूनियन (आजसू) की गठबंधन सरकार बनी। जमशेदपुर से सांसद श्री अर्जुन मुंडा तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहली बार वह 18 मार्च 2003 को और दूसरी बार 12 मार्च 2005 को राज्य के मुख्यमंत्री बने थे ।

भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी की श्री अर्जुन मुंडा को चुनौतियों से जूझने की सलाह

प्रिय श्री अर्जुन जी,

मैं अपनी ओर से तथा देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से आपको एक बार फिर से झारखण्ड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई देता हूं। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपके शपथ–ग्रहण समारोह में भाग लेता। परन्तु नागपुर में मेरे निवास स्थान पर गणेश चतुर्थी समारोह के कारण राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर पार्टी की सफलता एवं राज्य में लोकप्रिय शासन की स्थापना के अवसर पर मैं अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ शामिल नहीं हो पाया हूं। मैं इस अवसर पर आपको अपनी शुभकमनाएं भेंट करता हूं और कामना करता हूं कि आप हर तरह से सफल हों तथा आपके नेतृत्व में बनी सरकार से झारखण्ड के लोगों को एक सुदृढ़, स्थिर और प्रभावकारी सुशासन प्राप्त हो। आदिवासी समुदाय ने सदा ही भाजपा और इसके सहयोगी दलों में अपना विश्वास व्यक्त किया है और मुझे विश्वास है कि आप उनकी वेदना और आकांक्षाओं का हर प्रकार से ख्याल रखेंगे।

झारखण्ड के लोगों को आपसे बड़ी आशाएं हैं तथा पार्टी की उम्मीद है कि आप हमारी आशाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भाजपा ने सदैव स्व–शासित राज्यों में उत्कृष्ट सुशासन देने के प्रयास पर बल दिया है और मुझे निश्चित विश्वास है कि आपकी सरकार झारखण्ड के लोगों को ''उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का शासन'' प्रदान करेगी। भाजपा की सुराज अथवा सुशासन की विचारधारा में अन्त्योदय की विचारधारा जन्मजात रूप से निहित है जिसके अन्तर्गत समाज के अपवंचित और असुविधावंचित लोगों तक लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी जाती है और हमें आशा है कि आपके नेतृत्व में झारखण्ड में बनी भाजपा–नीत सरकार बेहतर प्रदर्शन कर दिखाएगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के निर्धन वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाना तथा नक्सलवादियों के खतरे पर विजय प्राप्त करना– ये दो चुनौतियां झारखण्ड सरकार के सामने खड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि पहले की सरकारों में आपके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता से इन दोनों चुनौतियों का सामना आप कारगर ढंग से कर लेंगे। मैं आपकी सफलता के लिए हार्दिक कामना करता हूं।

आपका

½fufru xMdj¼

चुनावों में भाजपा का परचम

भाजपा 9 राज्यों में सत्ता में है। लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी है। कुछ लोग भाजपा की प्रगति को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं वे वास्तव में वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। भाजपा की जीत का सिलसिला लगातार जारी है।

if'pe cxky में कलकत्ता म्युनिसिपल चुनाव में भाजपा ने तीन स्थानों पर जीत दर्ज की।

NŸkhl x< के सरगुजा जिले में भटगांव विधानसभा उपचुनाव में भाजपा विजयी रही।

vk/kçn'k में जुलाई 2010 में शहरी निजामाबाद उपचुनाव में भाजपा के ए. लक्ष्मीनारायण ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डी. श्रीनिवास को पराजित किया।

म.प्र. निकाय चुनाव

नगरीय निकाय चुनाव में मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 7 नगर निगमों पर जीत दर्ज की।

कर्नाटक

विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 10 स्थानों पर जीत दर्ज की

गत 21 दिसम्बर को कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन ने क्रमशः 10 और 5 सीटों पर जीत हासिल की। 10 सीटें जीतने के बाद विधानसभा के ऊपरी सदन में भाजपा के सदस्यों की संख्या 34 हो गई है। भाजपा ने अपनी चार पुरानी सीटें बरकरार रखी है और छह नई सीटें जीती है। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस अपनी पुरानी 19 सीटों में से मात्र 10 सीटें ही जीत पाई है। चुनाव 23 सीटों के लिए हुआ, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने एक–एक सीटें निर्विरोध हासिल कर ली थी।

५४ वर्ष में बेंगलूर में पहली बार भाजपा का महापौर

बेंगलूर दो साल पहले कर्नाटक की सत्ता हासिल कर दक्षिण में सरकार बनाने का रिकार्ड बनाने वाली भाजपा ने एक बार फिर इतिहास बना दिया। बेंगलूर नगरपालिका के 54 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा का महापौर बना। 198 सदस्यीय वृहत् बेंगलूर महानगरपालिका के लिए 28 मार्च को हुए चुनाव में भाजपा ने 110 सीटें अपने नाम की। कांग्रेस को 60 और किंगमेकर की भूमिका में आने की उम्मीद पाले बैठे जनता दल–सेक्युलर को महज 14 सीटें मिलीं।

कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा की जीत

कर्नाटक विधानसभा की दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा और जद(एस) ने एक–एक जीतकर कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। पूर्व मुख्यमंत्री धरम सिंह के पुत्र अजय सिंह लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचने में विफल रहे। कर्नाटक विधानसभा की कादुर और गुलबर्गा दक्षिण सीटों के लिए गत 13 सितम्बर को उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस की स्थिति गत वर्ष भाजपा के सत्ता में आने के बाद

से लगातार कमजोर हुई है। कादुर सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली है। दूसरे नंबर पर जद (एस) रही।

राजस्थान निकाय चुनाव में खिला कमल

बेलगाम महंगाई और राजस्थान की जनविरोधी सरकार से त्रस्त जनता ने राज्य की बीस महीने पुरानी कांग्रेस सरकार को नकार दिया है। विदित हो कि राजस्थान में हाल ही में सम्पन्न हुए निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम फहराया। भाजपा ने 126 में से 57 निकायों पर अपना कब्जा जमा लिया। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को 49 निकायों में ही बोर्ड बनाने का मौका मिला। दो निकायों में बसपा और एक में राकांपा का अध्यक्ष चुना गया है जबकि 17 स्थानों पर निर्दलीय पालिकाध्यक्ष बने।

केन्द्र शासित दादर-नागर हवेली एवं दमन-द्वीव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत

भारतीय जनता पार्टी को दादर–नागर हवेली एवं दमन–द्वीव के स्थानीय निकाय चुनावों में भारी विजय प्राप्त हुई। दादर–नागर हवेली के स्थानीय निकाय की कुल 22 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को 17 सीटों पर विजय हासिल हुई जबकि कांग्रेस मात्र 5 सीट पर ही विजय हासिल कर सकी है। साथ ही, 114 ग्राम पंचायत और 11 जिला पंचायत के हुए चुनावों में 70 ग्राम पंचायत और 8 जिला पंचायत में भाजपा को जीत हासिल हुई। इसी तरह, दमन एवं द्वीव में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी कुल 34 सीटों में से 18 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की है जबकि कांग्रेस को 3 और निर्दलियों को 12 सीटों पर विजय हासिल हुई है।

गुजरात: कठलाल विधानसभा उपचुनाव

भाजपा ने कांग्रेस को दी करारी शिकस्त

गुजरात में कांग्रेस के अभेद्य गढ़ कठलाल को ढहाते हुए भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव जीत लिया। आजादी के बाद इस सीट पर भाजपा की यह पहली जीत है। भाजपा के कानूभाई डाभी ने कांग्रेस के घेलाभाई झाला को 21547 मतों के अंतर से पराजित किया है। विदित हो कि यह सीट कांग्रेस विधायक गौतमभाई झाला के निधन के बाद खाली हुई थी।

13 सितंबर को कठलाल में उपचुनाव हुआ था और 17 सितंबर को घोषित हुआ। खास बात यह है कि उपचुनाव में भाजपा को निर्वाचन क्षेत्र के 65 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट दिए।

छह नगर निगमों पर भाजपा ने लहराया परचम

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 12 अक्टूबर को छह नगर निगमों के चुनावों में जीत हासिल करते हुए इन पर अपना कब्जा बरकरार रखा और केवल एक नगर निगम को छोड़कर शेष सभी पर दो तिहाई बहुमत से विजय प्राप्त की। भाजपा की इस जीत से कांग्रेस को करारा झटका लगा।

बिहार विधानसभा चुनाव

एनडीए की शानदार जीत

बिहार के 15वें विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल(यूनाइटेड) शामिल है, ने अभूतपूर्व जीत हासिल कर नया इतिहास रच दिया। वहीं लालू–पासवान को भारी झटका लगा और कांग्रेस की हालत खराब हुई। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजग को तीन चौथाई बहुमत मिला। उसके 206 उम्मीदवार जीत गये। जदयू ने सर्वाधिक 115 सीटें हासिल की जबकि भाजपा ने 91 सीटों पर जीत दर्ज की। राजग गठबंधन के तहत जदयू ने कुल 243 सीटों में से इस बार 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि भाजपा ने 102 सीटों पर। इस चुनाव में लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की पार्टी ने गठजोड़ कर चुनाव लड़ा था। राजद–लोजपा गठबंधन को

कुल 25 सीटें प्राप्त हुई जिसमें से राजद को 22 सीट तथा लोजपा को तीन सीटें मिली। कांग्रेस को भी करारा झटका लगा और उसे केवल चार सीटें ही मिली हैं जबकि पिछली बार उसे नौ सीटें मिली थीं। वाम दलों ने इस बार तालमेल कर चुनाव लड़ा था लेकिन वह भी काम नहीं आया और केवल एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। निर्दलीय व अन्य उम्मीदवारों ने कुल आठ सीटों पर जीत दर्ज की।

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। 2005 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा सबसे ज्यादा फायदे में रही। गौरतलब है कि 243 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए हुए राजग गठबंधन के तहत पिछली बार की तरह भाजपा ने 102 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसमें भाजपा को 91 सीटें मिली, जबकि पिछली विधानसभा में उसके पास मात्र 55 सीटें थीं। पार्टी को 36 अतिरिक्त सीटें मिली। भाजपा का स्ट्राइक रेट (सफलता की दर) 89.21 प्रतिशत उल्लेखनीय रहा।

◆ ● ◆

मोर्चा एवं प्रकोष्ठ

प्रकोष्ठों की प्रथम बैठक
सब के कार्य का ऑडिट होगा

गत 21 सितम्बर 2010 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के नव–नियुक्त राष्ट्रीय संयोजकों व सह–संयोजकों की प्रथम बैठक पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय अशोक रोड में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के उदघाटन भाषण से प्रारम्भ हुई। श्री गडकरी ने कहा कि प्रकोष्ठों का गठन पार्टी को और अधिक व्यापक व सर्वस्पर्शी बनाने की दृष्टि से किया गया है। यह पद नहीं दायित्व है और सब को अपने दायित्व के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रकोष्ठों के काम का प्रति मास मूल्यांकन होगा और हर तीन मास में समीक्षा बैठक की जायेगी। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी के कार्य निष्पादन का ऑडिट होगा। श्री गडकरी ने कहा कि पार्टी को 2014 के चुनाव तक अपना मत प्रतिशत 10 प्रतिशत बढ़ाना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह आज ही से इस संकल्प की प्राप्ति के लिये कमर कस लें।

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बाळ आपटे सांसद, राष्ट्रीय महामन्त्री संगठन श्री राम लाल, राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा मुख्यालय प्रभारी श्री श्याम जाजू तथा मोर्चों व प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय समन्वयक श्री महेंन्द्र कुमार पाण्डे उपस्थित थे।

भाजपा आर्थिक मंच का उद्घाटन

आर्थिक नीति के तीन स्तम्भ
राष्ट्रीयता, सुशासन और अन्त्योदय

गत 25 अक्तूबर को भाजपा के आर्थिक फोरम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि ''राष्ट्रीयता, सुशासन और अन्त्योदय भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति के तीन स्तम्भ हैं।'' भाजपा एक आधुनिक पार्टी है जो एक ऐसे आर्थिक मॉडल को तैयार करना चाहती है जो गरीबों के लिए कल्याणकारी हो, जिसे लोगों का समर्थन प्राप्त हो और जिसमें सुधार किया जा सके। इस आर्थिक विकास मॉडल के दो प्रमुख तत्व प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता हैं और आर्थिक फोरम को इस सम्बंध के हर पहलू में विस्तार से जाना चाहिए तथा तदनुसार 'स्थिति पत्र' तैयार करना चाहिए।

श्री गडकरी ने बल दिया कि अर्थव्यवस्था के विकास में सरकार–निजी भागीदारी मॉडल का एक विशेष महत्व है क्योंकि इससे व्यावहारिक ढांचा खड़े करने की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से सरकारी वित्त विषमता की खाई को पाटा जा सकता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा का मानना है कि सभी को आर्थिक न्याय प्रदान करते हुए भारत एक सुदृढ़ आर्थिक शक्ति बन सकता है जिससे अंततः गरीबी और अमीरी के बीच की हर प्रकार की असमानता को दूर किया जा सकता है।

दिनभर चली चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री यशवंत सिन्हा ने भाजपानीत–एनडीए सरकार द्वारा अपने शासनकाल में उठाए कदमों का उल्लेख किया। फोरम के संयोजक और राज्यसभा सांसद श्री प्रकाश जावडेकर ने भी अपने विचार रखे। भाजपा ने विभिन्न विषयों पर आठ उप–समूह बनाए हैं जिनमें मेक्रोइकानामिक्स, विकास और वृद्धि रणनीति, कृषि अर्थव्यवस्था, सामजिक ढांचा, भौतिक ढांचा, रोजगार और श्रम, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और निवेश; प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और नगर और ग्रामीण विकास आर्थिक फोरम के दायरे में शामिल किया गया है।

भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक : मुम्बई

नवगठित भाजपा महिला मोर्चा की प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मुम्बई में 29 और 30 सितम्बर 2010 को आयोजित की गई। 30 सितम्बर 2010 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने महिला मोर्चा की प्रथम वेबसाईट www.bjpmahilamorcha.com का उद्घाटन किया। भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सम्बोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा– ''हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें आज अपने देश में फैली राजनीतिक अविश्वनीयता पर विजय पानी है। महिलाएं हमारे राष्ट्र की नियति को बदलने में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

भाजयुमो : राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक

भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति सह अभ्यास वर्ग का आयोजन 12, 13, 14 सितम्बर, 2010 को रामभाऊ म्हालगी प्रबोधनी, मुम्बई में संपन्न हुआ। 14 सितम्बर को राष्ट्रीय कार्यसमिति का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने किया। उद्घाटन सत्र में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव व युवा मोर्चे की सह प्रभारी सुश्री वाणी त्रिपाठी ने नितिन गडकरी जी का साक्षात्कार लिया।

अनुसूचित जाति मोर्चा

रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट को लागू नहीं होने देंगे

भाजपा के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का अभिनन्दन अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा. सत्यनारायण जटिया ने फूलमालाओं एवं अंगवस्त्र भेंट कर किया। अभिनन्दन कार्यक्रम में नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ही आगे लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट संसद में रखे जाने पर हम इस रिपोर्ट को लागू नहीं होने देंगे। भाजपा इस रिपोर्ट का डटकर विरोध करेगी।

सुशासन प्रकोष्ठ

भाजपा का 'सुशासन' पर मंत्रीस्तरीय सम्मेलन

भारतीय जनता पार्टी 5–6 जून, 2010 को मुंबई में सुशासन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। 'सुराज–संकल्प' के रूप में नामित इस सम्मेलन में कल्याण तथा विकास संबंधी कुछ उल्लेखनीय और अभिनव पहलों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने इस कन्वेंशन का उद्‌घाटन किया जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य वक्तव्य दिया। इस कन्वेंशन में विभिन्न राज्य सरकारों ने कल्याण और विकास की अभिनव पहलों की प्रस्तुति भी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने शासक दल – प्रतिपक्षी दल के बीच अंतर्संबंध पर भाषण दिया। पार्टी संगठन के बीच संबंधों पर एक पेनल चर्चा हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेतागण – यथा महासचिव श्री जगत प्रकाश नड्डा तथा अखिल भारतीय सचिव श्री भूपेंद्र यादव, नवगठित गवर्नेंस सेल के संयोजक श्री मनोहर परिकर की अध्यक्षता में एक टीम और श्रीमती निर्मला सीतारमण, विनय सहस्रबुद्धे ने भी इस कन्वेंशन को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

भाजपा किसान मोर्चा पदाधिकारी बैठक

सीड बिल का विरोध करेगी भाजपा

गत 10 अगस्त 2010 को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की पदाधिकारी एवं प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हिमाचल सदन में सम्पन्न हुई। जिसका उद्‌घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने दीप प्रज्जवलित कर किया। उद्‌घाटन के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री वियज गोयल, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सतपाल मलिक एवं इस बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकड़ ने की। श्री गडकरी ने कहा कि अगर इस देश के किसानों की बदहाली को सुधारना है, तो इस सरकार को सिंचाई की व्यवस्था को दुरूस्त करना होगा। कहीं पानी के अभाव मे फसल सूख जाती है, तो कहीं बाढ़ आने पर फसल गल जाती है। लेकिन दोनों का खामयाजा इस बेचारे किसान को ही झेलना पड़ता है।

दिल्ली : झिंझौली प्रशिक्षण शिविर

राजनीतिक दक्षता के लिए अध्ययन और अभ्यास जरूरी

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित, तीन दिवसीय अभ्यास वर्ग का उद्‌घाटन दिल्ली के निकट झिंझौली गांव में 9 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। उद्‌घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि पार्टी ने जो कल्पना इंदौर के

राष्ट्रीय अधिवेशन में की थी उसे आज दिल्ली भाजपा की इकाई ने साकार किया है। उन्होंने प्रशिक्षण की धारणा स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यवसाय या प्रोफेशन में यदि दक्षता पाना चाहता है तो उसे लगातार अध्ययन, अभ्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है।

भाजपा पूर्वोत्तर सम्पर्क प्रकोष्ठ

गत 23 अगस्त 2010 को भाजपा पूर्वोत्तर सम्पर्क प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मुझे इस नवगठित प्रकोष्ठ में भाग लेते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे लगता है कि हमें इस प्रकोष्ठ का बहुत पहले गठन करना चाहिए था। हमारे पास अनेक प्रकोष्ठ हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारे पास क्षेत्र–विशिष्ट प्रकोष्ठ नहीं हैं। परन्तु भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को यह नया कदम उठाने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

मीडिया प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला सम्पन्न

भारतीय जनता पार्टी की दो–दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला 13 व 14 सितम्बर, 2010 को सम्पन्न हुई। यह कार्यशाला दिल्ली के रफी मार्ग, स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित थी। इस कार्यशाला में सभी प्रदेशों से प्रदेश मीडिया प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रदेश स्तर से इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में होने वाली चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकृत नेतागण सम्मिलित हुए। इस कार्यशाला का शुभारंभ 13 सितम्बर, 2010 को प्रातः 11 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने सम्बोधित किया। उन्होंने अपने उद्‌बोधन में वर्तमान राजनीति एवं भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ की भूमिका विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे।

विशेष सहयोग निधि अभियान का शुभारम्भ

भरोसेमंद जनशक्ति के साथ भरोसेमंद धनशक्ति भी जरूरी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पार्टी मुख्यालय में 30 जून 2010 को धन संग्रह हेतु विशेष सहयोग निधि अभियान के अन्तर्गत "जीवन संकल्प योजना" का शुभारंभ किया। श्री गडकरी ने भाजपा आजीवन सहयोग निधि के प्रभारी श्री मांगेराम गर्ग को 1 लाख रूपये का चैक व संकल्प पत्र सौंप कर जीवन संकल्प योजना की प्रथम सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ

कमजोर वर्गों में गतिविधियां बढ़ाने की आवश्यकता

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने ''मानवाधिकार आंदोलन : गलत धारणा को दुरूस्त करना'' विषय पर विचारगोष्ठी का उद्‌घाटन किया। अपने प्रमुख भाषण में श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा का मानवाधिकार प्रकोष्ठ को समाज के कमजोर वर्गों– जैसे महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों में काम करना चाहिए। हमारे समाज के इन वर्गों के लोगों का लम्बे समय से शोषण होता रहा है, अतः इन लोगों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

प्रदेशों से

मध्य प्रदेश

कार्यकर्ता वंदन और जनता अभिनंदन, कार्यकर्ता गौरव दिवस सम्पन्न

29 नवंबर, 2010। यह तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं भारतीय राजनीति के लिए चिरस्मरणीय रहेगा। इस दिन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर इतिहास रचा गया। प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में पांच साल पूरे करने वाले भाजपा नेता श्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मान में आयोजित 'कार्यकर्ता गौरव दिवस' कार्यक्रम में ढाई लाख कार्यकर्ता जुटे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने विश्वास के साथ कहा कि देश में यदि किसी राजनैतिक दल में लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां और तासीर है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यहां अपने कार्य के बल पर अदना सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां तक की प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ऐसा देश के सबसे बडे माने जाने वाले दल कांग्रेस में कभी संभव नहीं है। उन्होंने शिवराजसिंह चौहान की जनोन्मुखी नीतियों और मेहनतकश परिवारों, महिलाओं, युवकों के हित में संचालित विकास कार्यक्रमों की भूरि–भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारी को तो भूतपूर्व बनना ही पड़ता है लेकिन कार्यकर्ता दायित्व हमेशा बना रहता है, वह कभी पूर्व नहीं होता है और पार्टी संगठन का आधार बनता है। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा और समाज में बेहतर परिवर्तन लाने के लिए राजनीति में आई है। मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता गौरव दिवस आयोजित करके एक अनोखी और देश में लोकतंत्र की बेहतरी के लिए विलक्षण पहल की है। कार्यक्रम को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्यप्रदेश के प्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार, राष्ट्रीय महासचिव सर्वश्री थावरचन्द गेहलोत और नरेन्द्रसिंह तोमर, भाजपा मध्यप्रदेश अध्यक्ष श्री प्रभात झा एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने संबोधित किया।

पंजाब

आतंकवाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा

पंजाब के अपने पहले दौरे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल के साथ एक सुर में कहा कि आतंकवाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन गया है। यह देश की एकता को खंडित कर रहा है। आतंकवादी पर्यटक के रूप में देश में घुसते हैं। सैकंड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात करते हैं। देश के कई हिस्सों में सरकार का शासन नहीं चलता। दुश्मन देश राकेट दागता है और केन्द्र सरकार खामोश बनी रहती है। भाजपा एवं शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के दोनों वरिष्ठ नेता भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. बलदेव प्रकाश की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे थे।

जम्मू-कश्मीर

राष्ट्रीय एकता रैली

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने जम्मू में राष्ट्रीय एकता रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा पाकिस्तान के साथ वर्तमान परिस्थिति में वार्ता पुनः शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। श्री गडकरी यहां (जम्मू) में दो दिवसीय दौरे पर आए थे। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि पाकिस्तान ने अभी आतंकवाद को समर्थन करना जारी रखा है फिर भी केन्द्र सरकार उससे वार्ता करने जा रही है।

माधोपुर : डा. मुखर्जी प्रतिमा का अनावरण

धारा 370 को खत्म करना ही डा. मुकर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने रावी नदी के तट पर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि श्री मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा आज देश के राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वर्णिम दिन है। आर.एस.एस. और भाजपा ने देश की जनता को राष्ट्रभक्ति के संस्कार दिए हैं। यह स्मारक इसका प्रतीक है और देश के करोड़ों नौजवान इस स्थान से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेंगे।

युवा जागर यात्रा, नागपुर

भाजपा पृथक राज्य विदर्भ का समर्थन करेगी

गत 14 मार्च को यशवंत स्टेडियम, नागपुर में आयोजित एक विशाल 'युवा जागर यात्रा' की रैली को सम्बोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने उपस्थित विशाल समूह को विश्वस्त किया कि कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार जब कभी भी तेलंगाना बिल संसद में पेश करेगी तो भाजपा एक अलग विदर्भ राज्य का समर्थन करेगी।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद पहली बार कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा मुस्लिम या किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया था। हम अल कायदा और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ हैं। हम उनके खिलाफ हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। कांग्रेस ऐसा ही कर रही है।

गुवाहाटी (असम)

तुष्टिकरण की नीति से देश को खतरा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति की आलोचना करते हुए 6 अप्रैल 2010 को कहा कि यह देश की एकता के समक्ष खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीति ने देश के ढांचे, इसकी एकता और अखंडता के टूटने का खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों को आश्रय देने को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना की।

चेन्नई प्रवास

21वीं शताब्दी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति होनी चाहिए

भाजपा अध्यक्ष श्री गडकरी ने अपने चेन्नई दौरे के दौरान 10 अप्रैल को हिन्दू ग्रुप आफ पब्लिकेशंस के पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुद्रास्फीति, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, इनके अगाऊ सौदे, महिला आरक्षण बिल और पार्टी पदों पर महिलाओं का एक-तिहाई कोटा, नक्सलवादियों की चुनौतियों, अयोध्या आदि अनेक विषयों पर बातचीत की। हम यहां 'हिन्दू' में 12 अगस्त को प्रकाशित टी. रामकृष्णन के लेख और बातचीत के प्रमुख अंशों का हिन्दी भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं:-

श्री गडकरी ने बताया कि हम महसूस करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह हमारी अस्मिता से जुड़ा विषय है। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से ही प्रेरणा मिलती रही है।

भाजपा के 52 वर्षीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति बननी चाहिए और मैं मानता हूं कि राजनीति तो सामाजिक–आर्थिक सुधारों का एक साधन है जिसके लिए 'सुशासन' पहली आवश्यकता है... हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन राज्यों में जहां हमारा शासन है वहां 'सुशासन' के द्वारा समाज के सभी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया का विकास होता रहे। हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 10000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूपीए की गलत आर्थिक नीतियों और कुशासन से ही मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कृषि तथा ग्रामीण भारत के प्रति उपेक्षा की भी आलोचना की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता यही है कि राजनीति सामाजिक–आर्थिक सुधारों का साधन बने। जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने राजनीति में काम करने का फैसला किया और सोचा कि मैं देश, समाज और गरीबों के लिए कुछ कार्य कर सकूं। मैंने आजीवन इसी सिद्धांत पर कार्य किया है। सौभाग्य से, मेरे पास बुनियादी ढांचे के कार्य का अच्छा अनुभव रहा है। 1995–99 में महाराष्ट्र में लोकनिर्माण कार्य मंत्री के रूप में मुझे मुम्बई–पुणे एक्सप्रेसवे और मुम्बई में लाईओवरों के निर्माण का अवसर मिला। वर्ली–बांद्रा सी–लिंक (जिसमें मुम्बई के पश्चिमी उपनगरों को शहर में जोड़ा गया) का कार्य भी मेरे समय में शुरू हुआ। मैंने 5 करोड़ ईक्विटी के साथ 8000 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य

किया था। मैं देश का प्रथम राजनीतिज्ञ बन पाया जिसने पूंजी बाजार से 4000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। मेरी सभी परियोजनाएं आर्थिक रूप से सफल रही। जब मैं विकास के बारे में सोचता हूं तो यह अनुभव मुझे मदद देता है।

मुझे लगता है कि उद्योग और कृषि महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास के लिए हमें पानी, बिजली, परिवहन और संचार की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए हमें बिजली, पानी, बीज और उर्वरक चाहिए। साथ ही, सिंचाई का भी महत्व है। दुर्भाग्य से, 1947 के बाद कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की घोर उपेक्षा हुई। आज भी हमारे सामने खड़ी समस्याएं कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण ही पैदा हुई हैं।

मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मैंने ग्रामीण क्षेत्रों पर कार्य शुरू किया। मैं न तो कार्पोरेट व्यक्ति हूं न ही उद्योगपति। मुझे बायो–डीजल, एथनाल, बायो–फर्टिलाइजर्स, बायो–मेथेनाइजेशन, सौर ऊर्जा और विद्युत पर कार्य करने का गहरा लगाव है। मेरा चिंतन है कि लोगों की आस्था दो चीजों के प्रति रहती है– सरकार और ईश्वर! परन्तु यहां एक तीसरी चीज भी है– आप सामाजिक–आर्थिक जीवन के निर्माता हो सकते हैं। मैंने अपने भाजपा मित्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मित्रों के साथ ''पूर्ति'' नाम का सहकारी भण्डार शुरू किया। अब इसकी बिक्री 35 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। सरकार के हस्तक्षेप के कारण हमने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मॉडल का चुनाव किया। हमारे पास तीन चीनी मिलें हैं। हम बायोमास से बिजली पैदा करते हैं– गन्ने के सूखे चूरे से 24.5 मैगावाट और चावल के छिलके से 8 मैगावाट का उत्पादन होता है। मेरा सपना है कि हम कृषि की बिजली और ऊर्जा सैक्टर की तरफ मोड़ पाएं।

मेरा सपना है कि हरित ईंधन एथनाल और इसकी तकनीक के आधार पर पूरी तरह से ईंधन चलाए जा सकें। आजकल मैं इसी कार्य में व्यस्त हूं। बुनियादी रूप से मैं बायोफ्यूल पर काम कर रहा हूं। डिस्टिलरी के कारण हमारे पास बायोमेथेनाइजेशन संयंत्र हैं। हम गन्ने से बायोमास बना रहे हैं। प्रमुख उत्पादन बिजली है; इसके उप–उत्पाद चीनी, एथनाल और बायो–'फर्टिलाइजर्स हैं। मैं इनके विकास में बहुत रूचि रखता हूं।

मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण है और हम राष्ट्रवादी भावना और विचार रख कर इस शताब्दी में समाज के हर क्षेत्र में विकास और प्रगति कर सकते हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर क्षेत्र में विकास में जुटी हैं जिसमें वह विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष बल देती है।

सुशासन विकास के लिए प्रथम आवश्यकता है। हमारी पार्टी में एक सुशासन प्रकोष्ठ है और हमने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर परिकर को प्रमुख नियुक्त किया है। पार्टी नौ राज्यों में शासन कर रही है। हमारी योजना है कि हम सभी सरकारों की योजनाओं का अध्ययन करें जिसमें वामपंथी और तमिलनाडु की सरकारें भी शामिल हैं। हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन सभी राज्यों में, जहां हमारा शासन है, वहां सुशासन के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को बढ़ा सकें।

दूसरी बात, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की है। हमने इसे शुरू कर दिया है। इस वर्ष हम 10000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखते हैं।

जहां तक तमिलनाडु के विकास की बात है, वहां पानी प्रमुख विषय है। नदियों को जोड़ने की परियोजना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। कावेरी से आप को केवल 800 टीएमसी पानी मिलता है। परन्तु नदियों को जोड़ने से आपको 4000 टीएमसी पानी मिल सकता है। अब गुजरात को देखिए, वह भाजपा शासित राज्य है, वहां हमने 20 प्रतिशत पानी उपलब्धता में बढ़ोतरी की

है। नर्मदा के कारण, गुजरात में कृषि विकास की दर 14 प्रतिशत हो गई है। भारतीय औसत ऋणात्मक 0.2 प्रतिशत है।

जहां तक पार्टी का सम्बंध है, हमारे पास अनेकों राजनैतिक योजनाएं हैं। व्यक्तिशः मैं महसूस करता हूं कि यूपीए की गलत आर्थिक नीतियों और कुशासन के कारण कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति हुई है। यह बात मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं। मैं राजनीतिक रूप से यह बात नहीं कह रहा हूं।

जैसा कि आप जानते हैं कि हम दूसरे देशों को 12.5 रुपए प्रति किलो चीनी का निर्यात करते हैं। डेढ़ वर्ष पूर्व सरकार ने निर्यात सब्सिडी और परिवहन सब्सिडी के रूप में 1.7 रुपए दिए। अब हम 28 रुपए से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी आयात करते हैं। हम विदेशों से लाल गेहूं 19 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहे हैं। परन्तु सरकार किसानों को 9.5 रुपए दे रही हैं। आवश्यक वस्तुओं में 4,50,000 करोड़ रुपए की कुल बिक्री होती है परन्तु वितरण 4500 करोड़ रुपए का होता है। 99.24 प्रतिशत सट्टेबाजी और हेराफेरी में चला जाता है। 2004 में सरकार ने कमोडिटी एक्सचेंज में आवश्यक वस्तुओं को जोड़ दिया। इसका लाभ उठाने वालों में जालसाजी, सट्टेबाजों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और कालाबाजारी करने वाले लोग ही तो हैं। किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाती हैं।

हरियाणा और पंजाब में, सरकार किसानों से 11.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदती है। आप देखेंगे कि एक महीने बाद खुदरा कीमतें 26 रुपए तक जा पहुंचेगी। सरकार सट्टेबाजी क्यों करने देती है? सरकार क्यों कमोडिटी एक्सचेंज में आवश्यक वस्तुएं जोड़ती हैं?

देश के कृषि क्षेत्र को कोल्ड स्टोरेज, प्री–कूलिंग प्लांट्स और गोदामों की जरूरत है। जहां तक मुझे जानकारी और आंकड़ों का पता है, हमारे पास अनाज रखने के लिए गोदामों की क्षमता मात्र एक–तिहाई है। सरकार ने कभी भी प्री–कूलिंग प्लांट्स, कोल्ड–स्टोरेज और कृषि–प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता नहीं दी।

'सिंचाई' राज्य सूची का विषय है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था; इसमें मैंने 60,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की थी। चार लेन वाली राष्ट्रीय हाईवेज का मैं प्रमुख सलाहकार था। उस समय गांवों को जोड़ने का प्रश्न उठा था, जो एक राज्य–विषय था। मैंने वाजपेयी जी को बताया था कि गांवों को न जोड़ पाने के कारण ग्रामीण भारत के लोगों को अनेक वर्षों से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने साहसिक निर्णय लिया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार देगी और यह 60,000 करोड़ रुपए की योजना बनी।

हमें सिंचाई को समवर्ती सूची में जोड़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि जिसमें राज्यों और केन्द्र सरकार 50–50 प्रतिशत का अंशदान दें। इसमें सिंचाई की दुगुनी क्षमता बनेगी जिससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान होगा हमारा सचमुच जोर कृषि और ग्रामीण भारत के विकास पर होना चाहिए। हम अपने शासित राज्य–बिहार में भरपूर कोशिश कर रहे हैं जहां जीडीपी विकास दर ऋणात्मक 0.5 प्रतिशत थी वहां अब बिहार में यह 11 प्रतिशत है। सभी भाजपा शासित राज्यों में जीडीपी विकास दर में वृद्धि हुई है। आज हम इसे और भी बढ़ाने की योजना तैयार कर रहे हैं। अब हम इस बात में व्यस्त हैं कि किस प्रकार से रोजगार की संभावनाएं बढ़ें, किस प्रकार से गरीबी का उन्मूलन हो और किस प्रकार से और राज्यों में जीडीपी में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति आय बढ़े।

21वीं शताब्दी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति सामाजिक–आर्थिक सुधार का साधन है। मैं अपने कैरियर के रूप में राजनीति का चुनाव नहीं कर रहा हूं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से प्रेरणा

मिलती रही है। मैं देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने अपना काम दीवारों पर पोस्टर चिपका कर और लिखने के कार्य से शुरू किया था। अब भी मैं वार्ड समिति स्तर पर काम करता हूं। यह सब कुछ भाजपा में ही सम्भव है कि मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी के सर्वोत्तम पद अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। दूसरी पार्टियों में यह बात सोची भी नहीं जा सकती। यहां तक कि मनमोहन सिंह भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने की बात सोच नहीं सकते। वह पद तो पारिवारिक रह गया है। निश्चित ही हमारी पार्टी और पार्टियों से अलग किस्म की पार्टी है।

देहरादून (उत्तराखण्ड): जनाक्रोश रैली

आतंकवाद और नक्सलवाद कांग्रेस की देन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने केंद्र की कांग्रेस नीति सरकार पर हमला बोलते हुए देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और महंगाई की समस्या के लिए कांग्रेस और उसकी नीतियों को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि पशुपति से तिरुपति तक माओवाद से खतरा बढ़ गया है। भगत सिंह कोश्यारी समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने चेताया कि सीमाओं की सुरक्षा खतरे में हैं। चीन की ओर से भारतीय सीमा पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या विकराल हो चुकी है। अफजल गुरु को फांसी की सजा में देरी की जा रही है। कांग्रेस अफजल के साथ दामाद जैसा व्यवहार कर रही है। श्री गडकरी दून के परेड मैदान में आयोजित जनाक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे।

लखनऊ : भाजपा महापौर सम्मेलन

गत 19 नवम्बर को लखनऊ में आयोजित भाजपा महापौर तथा नगर–निगमों के पदाधिकारियों के द्वि दिवसीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने जोरदार अपील की कि आज हमारी आवश्यकता यह है कि हम सभी अपने शहरों के विकास के लिए दूरदृष्टि अपनाएं, सामूहिक राजनीतिक इच्छा से काम करें और भारत के शहरों को और बेहतर बना कर उन्हें रहने योग्य बनाएं। इसके लिए हमें अपने नगरों में विश्व–स्तर का बुनियादी ढांचा खड़ा करना होगा और जनजीवन को ऐसा बेहतर बनाना होगा जिसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए नवीनतम विकास के विचारों को प्रस्तुत करना होगा।